



Sara Ali Khan Reveals If social Media...

नौकरशाही



डॉ. वजेश मिश्र

महत्वाकांक्षी होना वैसे तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कहते हैं, 'अति सर्वत्र वर्जयेत'। पिछले कुछ वर्षों में अति महत्वाकांक्षा ने सिस्टम की चुनौतियाँ हिलाकर रख दीं। कई गंभीर सवाल खड़े हुए। इतना पढ़-लिख कर ऊँचा मुकाम हासिल करने के बाद आखिर क्या चाहिए? क्यों कुछ लोग मान-सम्मान की चिंता किए बिना कालिख पुतवाने को तैयार हैं। अब भी हालात कमोबेश यथावत हैं। ऐसे माहौल में एक चर्चित नौकरशाह की दोबारा सक्रियता फिर चर्चा का विषय बनी हुई है। आखिर क्या चल रहा है अंदरखाने, जानें द फोटोन न्यूज के एक्जीक्यूटिव एडिटर की कलम से।

गुरु कुछ बेचैन थे। किसी ने कान फूँक दिया था। पूजा का 'फल' मिलने वाला है। सिस्टम में फिर 'सिंचम' बनने की जोर-जुगत लगाई जा रही है। गुरु को यह बात हजम नहीं हुई। कृष्ण जन्मस्थान पर साधना और ऐसा चमत्कार? गुरु को यह कर्तई बर्दाश्त नहीं था। लिहाजा, सामने पड़ते ही दर्द की पोटली खोल दी। बताओ यार! यह तो हद है। भला ऐसा कोई करता है। जिस ज्वालामुखी के लावा से धरती लाल हो गई, फिर वहीं आशियाना बनाने की जिद। अब तक गुरु की गोल-गोल बातें आधी-अधूरी ही पल्ले पड़ रही थीं। पूरी कहानी तक पहुँचने के लिए धैर्य बनाए रखने की जरूरत थी। गुरु ने बात जारी रखी। कहा- अति महत्वाकांक्षा हमेशा भारी पड़ती है। क्या भूल गए वह दिन जब उस कालखंड का प्रवर्तन हुआ था? एक के बाद एक गले में ऐसी फांस कसी कि पूरी नौकरशाही हिल उठी। क्या मैडम, क्या हुक्मरान, सब कोठरी तक पहुँच गए। बड़े-बड़े नाम अर्थ से सीधे फर्श पर आ गए। कितनी कठिनाई में दिन और रातें कटीं, यह



प्रतीकालक रूप से एआई से बनाई गई काल्पनिक तस्वीर

भोगने वाले की अंतरात्मा जाने। फिलहाल राहत जरूर है, लेकिन शिकंजा पूरी तरह छूटा नहीं है। बावजूद पुरानी गलती दोहराने

की कवायद हो रही है। इन्हें फिर वहीं सब चाहिए। वैसा ही काम, वही रुतबा और वही ऑफिस...। गुरु का दर्द दूर करने के लिए

पूछ लिया, 'क्या हुआ गुरु साफ-साफ बताइए' गुरु बोले- एक मैडम को फिर ख्याब आ रहे हैं। गोलबंदी शुरू हो गई है। बालू,

पत्थर मिलाकर महल खड़ा करने का सपना है। दरअसल, गुरु नहीं चाहते थे, फिर माहौल बिगड़े। बात कोर्ट-कचहरी और गवाही तक पहुँचे। लिहाजा अनिष्ट की आशंका से उद्बलित हो गए थे। डाँड़स बंधाते हुए कहा- सिस्टम से गलती नहीं होगी गुरु। काहे परेशान हुए जा रहे हैं? गुरु बोले- महोदय यही सिस्टम पहले गच्चा खा चुका है। हम नहीं चाहते कि फाइल लेकर फिर दौड़ लगे। ऐसे में अगर मौजूदा दौड़ नहीं थमी तो परिणाम यथावत आ सकते हैं। यह समझ आनी चाहिए कि संकट टला नहीं है। नजर, नजरिया और हालात एक जैसे हैं। खदान में घुसने पर हाथ काले होने का अंदेश है। बेहतर होगा, ख्याब को अमलीजामा पहनाने की कसरत बंद करें। फिलहाल कमान काबिल हाथों में है। व्यवस्था में शांति बनी रहे। इसी में सबकी भलाई है। गुरु थोड़े शांत लग रहे थे। सान्निध्य से तनाव बढ़ने का डर था। लिहाजा हाथ जोड़े और दरबार से निकल पड़ा। मन-मस्तिष्क में एक के बाद एक शब्द कौंध रहे थे। पूजा, फल, कसरत, महत्वाकांक्षा...।

SHARE	
सेंसेक्स	: 75,364.69
निफ्टी	: 22,904.45

SARAF	
सोना	: 8,575
चांदी	: 108.00

(नोट : सोना 22 कैरेट प्रति ग्राम)

BRIEF NEWS

मेरी टिप्पणी को गलत तरीके से किया गया पेश : सीजेआई

NEW DELHI : कोकरोव वाले विवाद पर चीफ जस्टिस सुर्वकांत ने अपना बयान जारी किया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुझे यह पढ़कर दुख हुआ कि मीडिया के एक हिस्से ने कल एक कुछ मामले की सुनवाई के दौरान मेरी मौखिक टिप्पणियों को किस तरह गलत तरीके से पेश किया है। मैंने विशेष रूप से उन लोगों की आलोचना की थी, जिन्होंने फर्जी और नकली डिग्रियों की प्रवेश से वकालत जैसे व्यवसायों में मदद किया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसे ही लोग मीडिया, सोशल मीडिया और अन्य प्रतिष्ठित व्यवसायों में भी घुसपैठ कर चुके हैं, इसलिए वे परजीवी की तरह हैं। चीफ जस्टिस ने अपने बयान में कहा है कि यह कहना पूरी तरह से बेवजियाद है कि मैंने हमारे देश के युवाओं की आलोचना की मुझे न केवल हमारे वर्तमान और भविष्य के मानव संसाधन पर गर्व है, बल्कि भारत का हर युवा मुझे प्रेरित करता है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारतीय युवाओं के मन में मेरे लिए बहुत आदर और सम्मान है और मैं भी उन्हें एक विकसित भारत के स्तंभों के रूप में देखता हूँ।

छत्तीसगढ़ के स्थायी डीजीपी बनाए गए अरुण देव गौतम

RANCHI : 1992 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अरुण देव गौतम को छत्तीसगढ़ का स्थायी पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) नियुक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ गृह विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक सिंह ने आज 16 मई को इसका आदेश जारी किया। वे पिछले 17 महीनों से प्रभारी डीजीपी के रूप में कार्य कर रहे थे। अरुण देव गौतम को 2010 में भारतीय पुलिस पदक, 2018 में विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और 2002 में कोसोवा में सेवा देने पर संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ संभालीं।

नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को प्रधानमंत्री ने किया संबोधित

पहले कोरोना, फिर युद्ध, अब ऊर्जा संकट से जूझ रही पूरी दुनिया : मोदी

NEW DELHI @ PTI :

शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नीदरलैंड के दौर के दौरान हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में दुनिया के मौजूदा हालात पर गंभीर चिंता जताई। मोदी ने कहा कि आज मानवता के सामने अनेक बड़ी चुनौतियाँ हैं। पहले कोरोना, फिर युद्ध और अब ऊर्जा संकट से जूझ रही है। ये दशक दुनिया के लिए आपत्तकों का दशक बन गया है। अगर हालात नहीं बदले तो बीते अनेक दशकों के काम पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी गरीबी के दलदल में फंस जाएगी। यदि दुनिया ने समय रहते इस चुनौती का समाधान नहीं किया, तो पिछले कई दशकों में हासिल की गई विकास संबंधी उपलब्धियाँ नष्ट हो सकती हैं। ऐसी विपन्न स्थिति में भारत वैश्विक विकास का इंजन बनेगा।

वर्तमान परिस्थितियों में लचीली व भरोसेमंद सप्लाई चेन की महसूस की जा रही जरूरत

भारत और नीदरलैंड मिलकर विकसित कर रहे पारदर्शी व विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला

मुक्त व्यापार समझौता लागू होने के बाद यूरोप का प्रमुख प्रवेश द्वार बन सकता नीदरलैंड



सांस्कृतिक प्रतीकों का विस्तार से किया उल्लेख

प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में दुनिया लचीली और भरोसेमंद आपूर्ति श्रृंखला (सप्लाई चेन) की आवश्यकता महसूस कर रही है। भारत और नीदरलैंड मिलकर पारदर्शी एवं विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता लागू होने के बाद नीदरलैंड यूरोप का प्रमुख प्रवेश द्वार बन सकता है। उन्होंने उल्लेख किया कि

मुख्य भूमि यूरोप में भारतीय मूल के लोगों का सबसे बड़ा समुदाय नीदरलैंड में निवास करता है। प्रधानमंत्री ने सांस्कृतिक प्रतीकों का विस्तार से उल्लेख करते हुए कहा, जिस प्रकार भारत कमल के लिए प्रसिद्ध है, उसी प्रकार नीदरलैंड टयूलिप के लिए प्रसिद्ध है। टयूलिप और कमल दोनों यह सिखाते हैं कि जड़ें वाह पानी में हों या मिट्टी में, सौंदर्य और शक्ति दोनों प्राप्त की जा सकती हैं।

नीदरलैंड की प्रगति में भारतीय समुदाय का महत्वपूर्ण योगदान

मोदी ने कहा कि नीदरलैंड आकर उन्हें भारत जैसा अनुभव हो रहा है। यहां की प्रगति में भारतीय समुदाय का महत्वपूर्ण योगदान है और इस पर हर भारतवासी को गर्व है। उन्होंने कहा कि यहां बसे भारतीय परिवारों की कहानियाँ केवल प्रवास की नहीं, बल्कि संघर्ष और सफलता की कहानियाँ हैं। समय बदला, देश बदले और पीढ़ियाँ बदलीं, लेकिन भारतीय संस्कार, परिवार व्यवस्था और सांस्कृतिक जुड़ाव आज भी जीवित हैं। यहां भारतीयों ने डच भाषा को अपनाया, लेकिन अपनी मातृभाषाओं और सांस्कृतिक परंपराओं को भी संजोकर रखा। भारतीय संगीत और संस्कृति आज नीदरलैंड के परिवारों तक पहुंच रही है।

मई में पूरी तरह बदला हुआ है मौसम का मिजाज

पांच जून तक झारखंड में प्रवेश कर सकता मानसून

PHOTON NEWS RANCHI :

झारखंड में मई के महीने में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदला हुआ नजर आ रहा है। राज्य के कई इलाकों में कहीं तेज हवाएं तो कहीं झमाझम बारिश ने गर्मी का असर कम कर दिया है। इसी बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने संभावना जताई है कि इस बार मानसून समय से पहले पहुंच सकता है। पांच से छह जून तक मानसून के झारखंड पहुंचने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार, इसमें चार दिन



आगे-पीछे होने की संभावना बनी रहती है। अगर पूर्वानुमान सही रहा, तो झारखंड में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष मानसून 12 दिन पहले पहुंचेगा। बता दें कि मई माह में झारखंड के कई इलाकों में लगभग हर दिन आंधी के साथ बारिश हो रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को दिया आदेश, पारा शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी

सहायक आचार्य के रूप में नियुक्त होंगे पारा शिक्षक

PHOTON NEWS RANCHI :

सुप्रीम कोर्ट ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत पारा शिक्षकों (सहायक अध्यापकों) को चरणबद्ध ढंग से सहायक आचार्य के रिक्त पदों पर नियुक्त करने का आदेश राज्य सरकार को दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पारा शिक्षकों के लिए विशेष रूप से प्रक्रिया शुरू की जाए। कोर्ट ने पारा शिक्षकों का सीधे नियमितीकरण करने से इनकार कर दिया, लेकिन राज्य को झारखंड प्राथमिक विद्यालय शिक्षक भर्ती नियमावली, 2012 और झारखंड प्राथमिक

सहायक आचार्य के कुल पदों में 50 प्रतिशत पद पारा शिक्षकों के लिए हैं आरक्षित



विद्यालय सहायक आचार्य संवर्ग नियमावली, 2022 के तहत पहले से बनाए गए वैधानिक भर्ती तंत्र

प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्ति केस : फैक्ट फाईंडिंग कमेटी को जेएसएससी ने सौंपी विस्तृत रिपोर्ट

RANCHI : शनिवार को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) ने प्रशिक्षित हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति 2016 मामले की जांच में जुटी फैक्ट फाईंडिंग कमेटी को विस्तृत रिपोर्ट सौंप दी। जस्टिस गौतम कुमार चौधरी के नेतृत्व में बनी वनमैन फैक्ट फाईंडिंग कमेटी में इस मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान रिपोर्ट

सौंप गई। इस दौरान राज्य सरकार की ओर से लाई गई रिपोर्ट में विभागीय पत्रांक नहीं होने के कारण इस कमेटी ने स्वीकार नहीं किया। रिपोर्ट को आगामी सुनवाई के दौरान उपस्थापित करने का निर्देश दिया गया है। इस मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 23 मई को निर्धारित की गई है।

पारा शिक्षकों का झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (जेटेट) उत्तीर्ण होना जरूरी है।

हेल्थ कंसर्न बड़े खतरे के तौर पर देखा जा रहा हाई ब्लड प्रेशर

अब बच्चों में भी हृदय संबंधी बीमारियों की वृद्धि ने बढ़ाई चिंता

PHOTON NEWS @ RESEARCH DESK :

मानव शरीर विज्ञानियों के अनुसार, विशेष पेशीय उत्तकों से बना हृदय शरीर का पंपिंग स्टेशन होता है। इसके फेलने और सिकुड़ने की प्रक्रिया के माध्यम से शरीर के सभी अंगों में समुचित तरीके से रक्त का संचार संभव हो पाता है। रक्त संचार के माध्यम से ही पावन क्रिया के बाद सभी पोषक तत्व अंगों में पहुंचते हैं और जैव क्रियाएं जारी रहती हैं। हृदय में किसी भी प्रकार का विकार जैव प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है। धड़कनों का बढ़े रहना और अचानक रक्त संचार में बाधा आना जिंदगी के लिए घातक हो जाता है। सामान्य रूप से ऐसी स्थितियाँ प्रौढ़वस्था में होती हैं। आज की अत्युत्थित जीवनशैली के कारण हृदय संबंधी बीमारियाँ युवाओं में भी होने लगी हैं। अब हाल में हुए रिसर्च से यह महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है कि बच्चों में भी हृदय संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। बच्चों में बढ़ती दिल की बीमारियों के लिए हाई ब्लड प्रेशर को बड़े खतरे की तौर पर देखा जा रहा है। द लैंसेट चार्ल्ड एंड एडोलसेंट हेल्थ जर्नल से जुड़े विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम ने इस विषय पर लंबे समय तक विशेषणात्मक स्टडी की है। जर्नल में प्रकाशित शोध संबंधी रिपोर्ट के अनुसार, पिछले दो दशकों में बच्चों और किशोरों में उच्च रक्तचाप के मामले लगभग दोगुने हो गए हैं।

लाइफस्टाइल में गड़बड़ी के कारण 3 से 5 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ना दुर्लभ कुछ बच्चों में होते हैं जन्मजात हृदय रोग और हार्ट की खराबी से संबंधित समस्याएं



2025 में छह प्रतिशत से अधिक वृद्धि

उच्च रक्तचाप के मामले में वृद्धि साल 2005 में 3.2 प्रतिशत से बढ़कर 2025 में छह प्रतिशत से अधिक हो गई है। रिपोर्ट में यह बताया गया है कि अगर समय रहते

अनुवांशिक बीमारी की स्थिति स्वाभाविक

बीते एक दशक के आंकड़े उदाहरण देते हैं तो पता चलता है कि न सिर्फ इन बीमारियों का खतरा तेजी से बढ़ा है, बल्कि कम उम्र वाले भी इसका शिकार होते जा रहे हैं। युवाओं और किशोरों में भी हार्ट अटैक और इससे जुड़ी मौत की घटनाएं सामने आ रही हैं। रांची के जाने-माने फिजिशियन और हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. अरुण सरकार के अनुसार, आम तौर पर 1 से 3 साल के बच्चों में हार्ट अटैक का जोखिम बहुत कम होता है। इस तरह के मामले काफी दुर्लभ माने जाते हैं। ये उम्र

चलने-फिरने, दौड़ने वाली होती है। लाइफस्टाइल में गड़बड़ी के कारण 3 से 5 साल के बच्चों में दिल का दौरा पड़ना बहुत दुर्लभ घायल हो गए हैं। सोशल मीडिया पर साझा किए गए दुर्घटना के फुटेज में दिखाया गया है कि रेलवे क्रॉसिंग पर वाहनों की एक कतार रुकी हुई थी, तभी एक मालगाड़ी ने एक नारंगी रंग की बस को टक्कर मार दी। टक्कर के कारण कई वाहन डरियर पर घिसटते हुए बस के साथ-साथ आगे बढ़ गए और बस में आग लग गई। टक्कर के बाद कई मोटरसाइकिल सवार भी सड़क पर गिरते हुए देखे गए।

बैंकोंक में मालगाड़ी ने बस को मारी टक्कर, 8 लोगों की चली गई जान

NEW DELHI : शनिवार को थार्लैंड की राजधानी बैंकोंक में एक ट्रेन की टक्कर एक बस से हो गई। ट्रेन बस को धकेलती रही। उसी समय बस में आग लग गई। हादसे में कम से कम आठ लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार, यह दुर्घटना दोफर बाद मध्य क्षेत्र में हवाई अड्डे के रेलवे स्टेशन के पास हुई। शहर की आपातकालीन सेवाओं, एरान मेडिकल सेंटर ने बताया कि कम से कम आठ लोगों की मौत हो गई और 20 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। सोशल मीडिया पर साझा किए गए दुर्घटना के फुटेज में दिखाया गया है कि रेलवे क्रॉसिंग पर वाहनों की एक कतार रुकी हुई थी, तभी एक मालगाड़ी ने एक नारंगी रंग की बस को टक्कर मार दी। टक्कर के कारण कई वाहन डरियर पर घिसटते हुए बस के साथ-साथ आगे बढ़ गए और बस में आग लग गई। टक्कर के बाद कई मोटरसाइकिल सवार भी सड़क पर गिरते हुए देखे गए।

नीट-यूजी 2026 : अब तक नौ आरोपी गिरफ्तार पेपरलीक : पुणे की शिक्षिका को सीबीआई ने किया अरेस्ट

AGENCY NEW DELHI :

शनिवार को सेंट्रल ब्यूरो का इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) की टीम ने नीट-यूजी 2026 पेपर लीक मामले में पुणे की एक और शिक्षिका को दिल्ली से अरेस्ट किया है। आरोपी की पहचान सीनियर बॉटनी टीचर मनीषा गुरुनाथ मांधरे के रूप में की गई है। आरोप है कि उसने परीक्षा से पहले छात्रों को बॉटनी और जूलॉजी के कई सवाल बताए थे। छात्रों को बताए गए अधिकतर सवाल 3 मई 2026 को आयोजित नीट परीक्षा के असली प्रश्नपत्र में थे। सीबीआई के मुताबिक मनीषा गुरुनाथ को एनटीए ने नीट परीक्षा में एक्सपर्ट के तौर पर नियुक्त

एनटीए ने एक्सपर्ट के रूप में किया था तैनात छात्रों को बताए बॉटनी-जूलॉजी के कई सवाल

किया था। उसके पास बॉटनी और जूलॉजी के प्रश्नपत्रों तक पूरी पहुंच थी। अब तक नौ आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जांच एजेंसी के अनुसार, अप्रैल 2026 में आरोपी टीचर ने पुणे की ही रहने वाली मनीषा वाघमारे के जरिए नीट अभ्यर्थियों को जुटाया। मनीषा वाघमारे को सीबीआई पहले ही 14 मई को गिरफ्तार कर चुकी है। सीबीआई का दावा है कि मांधरे ने अपने पुणे स्थित घर पर स्पेशल कोचिंग क्लास चलाई।

गुमनाम है कोई...

चंदनगढ़ स्टेशन पर जब रात को ट्रेन रुकती है तो वहाँ उतरने वाले नौजवान को सलाह दी जाती है कि इतनी रात गए उसी भूत बंगले में न जाना ठीक नहीं। अपने प्रेम में पीटा चाहता है कि ये नौजवान अफिल्ल का नायक विजय (विश्वजीत) है। स्टेशन पर विजय को ले जाने के लिए आए डॉक्टर पाण्डेय (मदनपुरी) बताते हैं कि बीस साल पहले विजय के दादा जी, फिर उससे पिता जी और आज हाल ही में उसके चाचा जी की हत्या हो चुकी है। डॉक्टर पाण्डेय,



वैभव मणि त्रिपाठी



SCAN ME

- हमें अपना फीडबैक, सुझाव या टिप्पणियां देने के लिए दिए गए बार कोड को स्कैन करें या मेल करें।
- आप हमें अपनी रचनाएं, कविता या आलेख भी भेज सकते हैं। जिसे हम अपने आने वाले अंक पर प्रकाशित करेंगे।

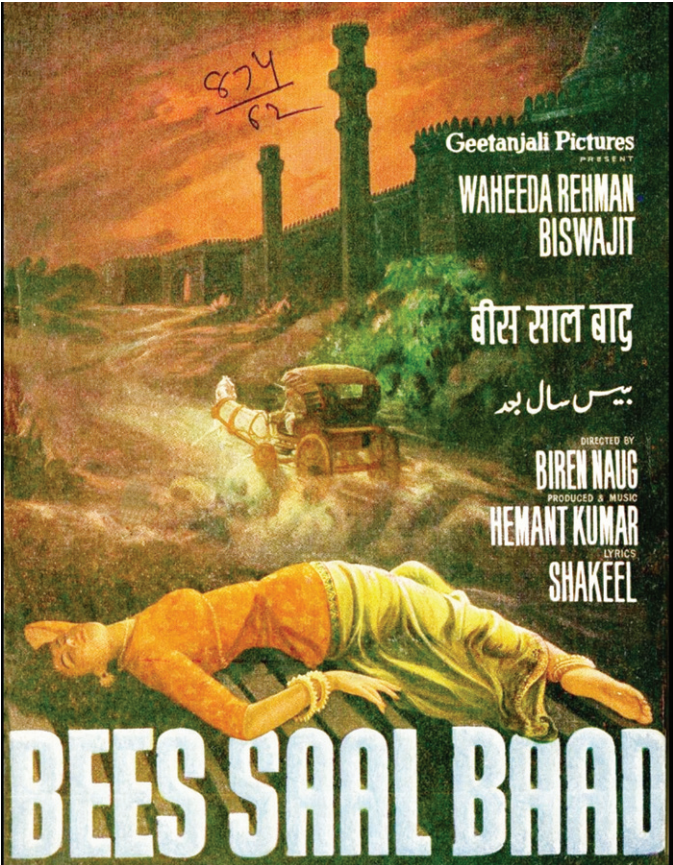
Email- thephotonnewsjharkhand@gmail.com

साल 1962 की सबसे सफल फिल्म 'बॉस साल बाद' गीतांजलि पिकर्स के बैनर तले बनी थी और ज्यारदार इंटरनेट से सेंस फिल्म के रिलीज की तारीख पहली जनवरी ही बताते हैं। बोरिंग नाग निर्देशित इस फिल्म की पटकथा ध्रुव चटर्जी और संवाद देव किशन ने लिखे थे। शकील बंद्योपी की लिखी गीतों ने निर्माता हेमंत कुमार से संपीत दिया और गीतों को आवाज दी हेमंत कुमार और लता मंगेशकर ने। फिल्म का छायांकन मार्शल ब्रैगैन्स ने और सम्पादन

केशन नंद ने किया।

नाटक विश्वज्योती की ये पहली हिन्दी फिल्म थी और इस फिल्म ने उस वर्ष की सबसे बड़ी हिट का दर्जा पाया। बॉलीवुड फिल्मों के स्टार विश्वज्योती को सबसे पहले गुरुदत्त ने हिन्दी सिनेमा साहब बीवी और गुलाम में भूतनाथ का रोल ऑफर किया। क्योंकि बॉलीवुड थिएटर में बिमल मिश्र की इस कालजयी कृति पर खेले जा रहे नाटक में विश्वज्योती भूतनाथ का चरित्र निभा रहे थे। इनका चयन, मीना कुमारी, अव्वरार अल्वी और गुरु दत्त ने नाटक देख कर किया, पर क्योंकि विश्वज्योती गुरुदत्त की प्रोडक्शन कंपनी के साथ पाँच साल के अनुबंध में बंधना नहीं चाहते थे इसलिए बात बनी नहीं। फिल्म से जुड़े अपने अनुभवों को याद करते हुए एक साप्ताहिक में विश्वज्योती ने

फिल्म के एक बहुत महत्वपूर्ण किरदार रामलाल के रूप में नजर आने वाले मनमोहन कृष्ण भारतीय सिनेमा के पुरोधाओं की श्रेणी में गिने जाते हैं। कई हिन्दी और पंजाबी फिल्मों में काम करने वाले मनमोहन कृष्ण ना सिर्फ अदाकारी के लिए जाने जाते हैं बल्कि अपने कैरियर के शुरुआती दौर में उन्होंने पाश्चात्यन भी किया है। 'धूल का फूल' के गीत 'तू हिन्दू बनेगा ना मुसलमान बनेगा' का प्रसिद्ध मनमोहन कृष्ण की हर घर का परिचित चेहरा बना दिया। अपने कैरियर में इन्होंने



यशराज फिल्मस् के लिए 'नूरी' फिल्म का निर्देशन भी किया। हिन्दी से लेकर पंजाबी फिल्मों दुनिया में अपनी प्रतिभा प्रतिभा का लोहा मनवाने वाले मनमोहन कृष्ण ने भीतक विज्ञान को पढ़ाई की थी और प्रोफेसर को नौकरी छोड़ कर फिल्मों में आये। फिल्म के गीतकार शकील बदायूनी की बात करें तो ये वो दौर था जब बदायूनी साहब अपनी रचनात्मकता को सर्वोच्च शिखर पर थे। उन्हें जले का कहीं दिल' गीत के लिए 'कहाँ' लगाता तीसरी बार फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया था। इससे पहले के दो वर्षों में वो क्रमशः 'चौहद्वी का चाँद हो' (चौहद्वी का चाँद) और 'हुस्न वाले तेरा जानना नहीं' (घराना) के लिए भी पुरस्कार प्राप्त कर चुके थे। 'बीस साल बाद' फिल्म को अपने बेहतरीन गीतों, संगीत और अदाकारी के लिए जाना जाता है। फिल्म में कैमरा तकनीक, पहली ही फिल्म में जबरदस्ती और भावप्रणव अभिनय के साथ अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज करवाते विश्वजीत

और अपनी निर्देशकीय क्षमता से हिन्दी सिनेमा पर अपनी गहरी छाप छोड़ते बॉक्स नाग के कुछ एवे फिल्म याद की जा सकेंगी। फिल्म में कुछ एक दृश्यों में कहानी झटके से आगे बढ़ती है, कुछ कड़ियाँ मिलाने का काम दर्शकों के जिम्मे रह जाता है और लक्ष्मण के रूप में काम करते फिल्म के संवाद लेखक देव किशोर जी जगह प्रवास करते हैं कि वो अपनी आँखों और भावभंगिमा से रहस्य गहरा सके, पर खास कामयाब नहीं हो पाते। फिल्म की कोई भी बात अधूरी रह जाती है अगर हम वहींदा रमनाम जो की बात ना करें। 'बीस साल बाद' विशेष रूप से उनकी फिल्म है 'राग माँद' पर आधारित उन पर फिल्माया गीत 'सपने सुहाने लड़कन के' आज भी उनके भावप्रधान नृत्य और अभिनय के फिल्म याद किया जाता है।

फिल्म यूट्यूब के साथ साथ एयरटेल एक्सट्रीम के एप पर उपलब्ध है और एयरटेल एक्सट्रीम पर बिना विज्ञापनों के देखी जा सकती है।

कविता



શોભા અક્ષર

तुम किसी को झुका दो

ताकत यह नहीं कि
तुम किसी को झुका दो
बल्कि यह कि
तुम किसी को उठने दो

कमजोर वही होता है
जो दूसरों की आजादी से डरता है

जब स्त्री आजाद होती है
पुरुष भी मुक्त होता है
पितृसत्ता के बोझ से
अपने डर से
अहंकार से

एक फेमिनिस्ट पुरुष जानता है
स्त्रीवाद सिर्फ औरतों का नहीं
समानता का आंदोलन है

वह चलता रहता है
सड़क पर, घर में, संसद में
हर जगह
स्त्रीवादी होने की कीमत चुकाते हुए

वह समझता है
समानता कोई उपकार नहीं
और आजादी
बाँटने से घटती नहीं
बल्कि बढ़ती है।

लेकिन मेरी मंजिल अभी आगे थी। अगले दिन सुबह-सुबह मैं विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पहुँचा। आराकू जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म पर तैयार खड़ी थी। इस रेलमार्ग के बारे में पहले ही सुन चुका था कि यह भारत के सबसे खूबसूरत ट्रेन रूट्स में से एक है। ट्रेन धीरे-धीरे शहर से बाहर निकली और कुछ ही देर में समुद्र पीछे छूट गया। मैदानों की जगह पहाड़ों ने ले ली और खिड़की के



करीब चार घंटे बाद ट्रेन आराकू स्टेशन पहुँची। छोटा सा स्टेशन, आसपास फैली हरियाली और पहाड़ों से उतरती ठंडी हवा—पहली ही नजर में यह जगह मन को सुकून देने लगी। स्टेशन के बाहर सड़क किनारे छोटी दुकानों से ताजी कॉफी की खुशबू हवा में घुल रही थी। आराकू अपनी आँगिनक कॉफी के लिए पुरी दुनिया में प्रसिद्ध है और यहाँ पहुँचते ही उसका एहसास होने लगता है। मैं जिस होमस्टे में ठहरा था, वह घाटी के



संजय शेफर्ड
नई दिल्ली

■ घुमक्कड़ की पाती

समुद्र, पहाड़ और आदिवासी जीवन



नहीं लगते, बल्कि एक-दूसरे में घुले हुए महसूस होते हैं।

शाम को मैं स्थानीय आदिवासी संग्रहालय पहुंचा। बाहर से साधारण दिखने वाला यह संग्रहालय भीतर आदिवासी संस्कृति की पूरी दुनिया समेटे हुए है। दीवारों पर बने चित्र, लकड़ी की मूर्तियाँ, पारंपरिक वाद्ययंत्र और मिट्टी के बर्तन इस क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बना देते हैं। संग्रहालय में घूमते हुए एहसास हुआ कि आराकू की धूमली खूबसूरती केवल उसकी घाटियों में नहीं, बल्कि उन लोगों में भी है जिन्होंने सदियों से प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीवन जीया है। अगले दिन मैं बोरों गुफाओं की ओर निकल पड़ा। आराकू से कुछ दूरी पर स्थित ये गुफाएँ पूर्वी घाट की सबसे प्रसिद्ध प्राकृतिक संचनाओं में गिनी जाती हैं। रास्ता घने जंगलों और पहाड़ी मोड़ों से होकर गुजरता है। कई जगह बादल इतने नीचे उतर आते कि लगता था मानो गाढ़ी धुंध के भीतर प्रवेश कर रही हो। बोरों गुफाओं के भीतर प्रवेश करते ही वातावरण अचानक बदल गया। ऊपर से टपकता पानी, चूना पत्थर से बनी विचित्र आकृतियाँ और हल्की रोशनी में बनती पछाड़ियाँ गुफाओं को रहस्यमय बना रही थीं। कहीं पत्थर शिवालिंग जैसे दिखाई देते, तो कहीं किसी मानव आकृति की तरह। स्थानीय लोग इन गुफाओं से जुड़ी कई लोककथाएँ सुनाते हैं, जिनमें आस्था और प्रकृति एक-दूसरे में घुली हुई

महसूस होता है। गुफाओं से लौटते समय मैं अनन्तगिरि की पहाड़ियों में कुछ देर रुका। सड़क किनारे छोटे ढाबों में बांस चिकन और स्थानीय व्यंजनों की खुशबू हवा में तैर रही थी। मैंने केले के पत्ते पर परोसा गया स्थानीय भोजन खाया। पहाड़ों में साधारण भोजन भी किसी विशेष अनुभव जैसा लगता है।

यात्रा के दौरान मैंने महसूस किया कि आरूक की सबसे बड़ी खूबसूरती उसकी सादगी है। यहां तेज संगीत, भीड़ और चमक-दमक कम दिखाई देती है। लोग धीरे-धीरे बोलते हैं, रास्ते शांत हैं और प्रकृति हर जगह प्रमुख भूमिका में है। शायद यही कारण है कि यहां आने के बाद मन अपने आप धीमा पड़ने लगता है। एक शाम मैं घाटी के एक छोटे से गांव तक पैदल चला गया। बच्चे खुले मैदानों में खेल रहे थे और महिलाएं घरों के बाहर बैठकर रहस्यपूर्ण का काम कर रही थीं। वहां किसी को जल्दी नहीं थी। शहरों की तरह यहां समय गड़ी से नहीं, सूरज और मौसम से चलता हुआ महसूस होता है। जब वापसी के लिए ट्रेन फिर पहाड़ों से नीचे उतरने लगी, तब मन बार-बार पीछे मुड़कर देखना चाहता था। धीरे-धीरे गांटियां दूर होती गईं, लेकिन भीतर एक गहरी शांति रह गई थी। शायद यही आरूक का सबसे बड़ा आकर्षण है- आप यहां कुछ दिनों के लिए आते हैं, लेकिन इसकी हरियाली, इसकी खामोशी और इसकी सरलता लंबे समय तक आपके भीतर बनी रहती है।

BRIEF NEWS

सीएम को विधायक ने लिखा पत्र, उर्दू शिक्षकों के पद सृजन की मांग

ARARIA : जोकोहाट के विधायक मो. मुर्शीद आलम ने बिहार के नवसृजित 208 महाविद्यालयों में उर्दू विषय के शिक्षकों का पद सृजित करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पत्र लिखा है। विधायक ने कहा है कि राज्य के सभी 38 जिलों में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उर्दू विषय की पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन नए महाविद्यालयों में उर्दू शिक्षकों के पद नहीं होने से छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। विधायक मो. मुर्शीद आलम ने मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में कहा कि राज्य के अन्य महाविद्यालयों में उर्दू विषय के शिक्षकों के पद पहले से सृजित हैं और हजारों छात्र-छात्राएं इस विषय की पढ़ाई कर रहे हैं। इसके बावजूद नवसृजित 208 कॉलेजों में उर्दू शिक्षकों का पद नहीं बनाया जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक है।

अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध चला बुलडोजर दो घर किए गए ध्वस्त

BETTIAH : पश्चिम चंपारण ज़िला के बलथर थाने स्थित नकुटवा दक्षिण टोला में आम गैरमज्रूआ भूमि से अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध बुलडोजर चला अतिक्रमण मुक्त की कार्रवाई की गई। शनिवार को उक्त कार्रवाई भूमि सुधार उप समाहर्ता के निर्देश पर सीओ प्रिया आयाणी ने की। सीओ प्रिया आयाणी के नेतृत्व में बलथर थानाध्यक्ष ओमप्रकाश गुप्ता, सिकटा व गोपालपुर थाने के पुलिस पदाधिकारी व सुरक्षा बलों समेत प्रभारी अंचल निरीक्षक सुनील कुमार, राजस्व कर्मचारी जयप्रकाश राम, रंजीत कुमार, अंचल अमीन व नीरज कुमार सिंह समेत कई तैनात थे।सीओ प्रिया ने बताया कि खाता-394,खेसरा-1979 आम गैरमज्रूआ किस्म की भूमि है, जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। बावजूद इस पर अवधिकशोर बैठा फुस की झोपड़ी व बाबूलाल बैठा नीचे ईंट का दिवाला व उपर कंकर्ट डालकर घर बना लिए थे।

एसएसबी ने पथराह में 235 लीटर शराब के साथ जब्त की बाइक

ARARIA : सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) 56 वीं वाहिनी की बाह्य सीमा चौकी फुलकाहा की विशेष गश्त कर रही टीम ने मध्य रात्रि नेपाल से तस्करी कर लाए जा रहे 235.8 लीटर शराब के साथ बाइक को जब्त किया गया। मध्य रात्रि को जब एसएसबी की टीम भारत नेपाल खुली सीमा पर गश्त कर रही थी तो पथराहा मेहता टोला के समीप नेपाल से एक बाइक आता दिखाई दिया। जिस पर एसएसबी की टीम ने घेराबंदी की तो तस्कर बाइक और शराब को छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाते हुए मौके से फरार हो गया। एसएसबी जवानों ने यह कार्रवाई भारतीय बोर्डर क्षेत्र में भारत-नेपाल सीमा रंथंभ संख्या 190/2 के नजदीक सी मोटर की दूरी पर की। एसएसबी ने दो तस्करी में प्रयुक्त दो साइकिल भी जब्त किया। जब्त शराब,बाइक और साइकिल को आवश्यक कामजी कार्यवाही के बाद एसएसबी द्वारा आबकारी विभाग अररिया के सुपुर्द कर दिया गया।

मंत्री विजय सिन्हा ने एआईएफ योजना की प्रगति को लेकर अधिकारियों के साथ की बैठक, कहा-

कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहा 'कृषि अवसंरचना कोष'

AGENCY PATNA : बिहार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने शनिवार को 'कृषि अवसंरचना कोष' (एआईएफ) योजना की प्रगति को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और उन्हें आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक के दौरान कृषि मंत्री ने योजना की प्रगति पर संतोष जताते हुए कहा कि एआईएफ योजना राज्य के कृषि क्षेत्र में बड़े बदलाव का माध्यम बन रही है। उन्होंने कहा कि इस योजना के जरिए बिहार में कृषि आधारभूत संरचना को मजबूत किया जा रहा है तथा किसानों को आधुनिक सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि कृषि अवसंरचना कोष एक केंद्रीय क्षेत्र की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में मध्यम और दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण उपलब्ध कराकर आधारभूत ढांचे का विकास करना है। योजना के



अधिकारियों के साथ बैठक करते कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा

तहत फसलों की कटाई के बाद बेहतर प्रबंधन, भंडारण तथा सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के निर्माण को बढ़ावा दिया जा रहा है। कृषि मंत्री ने जानकारी दी कि 4 नवम्बर 2025 तक बिहार में इस योजना के अंतर्गत कुल 2045 परियोजनाओं को स्वीकृति दी जा चुकी है। इन परियोजनाओं के लिए 1650.37 करोड़ रुपये की

राशि मंजूर की गई है। उन्होंने बताया कि राज्य में सबसे अधिक निवेश भंडारण क्षमता बढ़ाने के क्षेत्र में हुआ है, जहां 834 गोदाम परियोजनाओं को स्वीकृति मिली है। वहीं खेती और कटाई के मशीनीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए 591 परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं। विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि

फसलों के मूल्य संवर्धन को ध्यान में रखते हुए बिहार में 315 प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित किए गए हैं। छोटे और सीमांत किसानों को आधुनिक कृषि उपकरण किराये पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 196 कस्टम हायरिंग सेंटर भी बनाए गए हैं। इसके अलावा योजना के तहत ई-मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, साइलो, पैक-हाउस,

कोल्ड चेन, लॉजिस्टिक्स सुविधाएं, पकने वाले कक्ष, जैविक इनपुट उत्पादन इकाइयां तथा स्मार्ट एवं सटीक कृषि जैसी आधुनिक व्यवस्थाओं को भी शामिल किया गया है। मंत्री ने कहा कि योजना के तहत दो करोड़ रुपये तक के ऋण पर अधिकतम सात वर्षों के लिए तीन प्रतिशत वार्षिक ब्याज छूट दी जाती है। एक आवेदक विभिन्न स्थानों पर अधिकतम 25 परियोजनाएं स्थापित कर सकता है। उन्होंने बताया कि दो करोड़ रुपये तक के ऋण पर 'सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट' योजना के तहत क्रेडिट गारंटी कवरेज भी उपलब्ध कराया जाता है। इसकी फीस का भुगतान सरकार अधिकतम सात वर्षों तक करती है, जिससे लाभार्थियों को किसी प्रकार की कोलैटरल या अतिरिक्त गारंटी देने की आवश्यकता नहीं होती।

फरियादियों से खचाखच भरा अंचल कार्यालय जनता दरबार में प्रशासन ने दिखाया एक्शन

AGENCY BETTIAH : अपनी जमीन, दारिखल-खारिज और सीमांकन विवादों के समाधान की आस लेकर शनिवार को बड़ी संख्या में लोग अंचल कार्यालय पहुंचे। जनता दरबार शुरू होते ही परिसर फरियादियों की भीड़ से भर गया। दरोगा यादव, गोरख चौधरी, गायत्री देवी, इंद्रभान राव, पंकज सिंह, विश्वनाथ महतो, संजल यासमीन, भारत शाह, रामबचन समेत कई लोगों ने अपनी समस्याएं प्रशासन के समक्ष रखीं और त्वरित कार्रवाई की मांग की। अंचल अधिकारी नीतेश कुमार सेठ की अध्यक्षता में आयोजित जनता दरबार में कुल 16 मामलों की सुनवाई हुई। इनमें 10 नए और 6 पुराने मामले शामिल थे। प्रशासन ने तेजी दिखाते हुए 6 मामलों का मौके पर ही निष्पादन



जनता दरबार में फरियादियों की समस्या सुनते अधिकारी

कर दिया, जबकि 3 मामलों में संबंधित कर्मियों को तत्काल कार्रवाई का निर्देश दिया गया। शेष मामलों में जांच नोटिस जारी कर अगली प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया गया। अंचल अधिकारी नीतेश कुमार सेठ ने कहा, 'भूमि विवादों में आपसी सहमति और पारदर्शिता सबसे जरूरी है, इससे लोगों को

जल्दी न्याय मिल सकता है।' वहीं नवनिर्गत थानाध्यक्ष इंद्रजीत पासवान ने कहा, 'लोग समय पर जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराएं ताकि मामलों का शीघ्र निष्पादन किया जा सके।' मौके पर राजस्व अधिकारी राहुल कुमार अग्रवाल, बड़ा बाबू ब्रजेश कुमार, विवेक कुमार समेत अंचल कार्यालय के कई कर्मी मौजूद रहे।

छपरा में ट्रक ने बोलेरो को मारी टक्कर, छह घायल

SARAN : छपरा-सिवान मुख्य मार्ग एनएच-531 पर रसूलपुर बाजार स्थित हनुमान मंदिर के समीप शनिवार को एक सड़क हादसा हुआ। एक तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से बोलेरो में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बोलेरो के परखच्चे उड़ गए। इस दुर्घटना में चालक सहित छह लोग घायल हो गए हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों और रसूलपुर थाना पुलिस की मदद से सभी घायलों को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, एकमा ले जाया गया, सभी का प्राथमिक उपचार किया डॉक्टरों के अनुसार सभी घायलों की हालत खतरे से बाहर है। घायलों की पहचान बक्सर जिले के बड़की नैनी गांव निवासी फकिर विजय शंकर साहनी, संजय राम, भिरू राम, दीपक राम, हर्देर राम और आदर्श कुमार के रूप में हुई है।

सड़क को लेकर मंत्री के खिलाफ ग्रामीणों का 21 दिवसीय आमरण अनशन हुआ शुरू

AGENCY BHAGALPUR : जिले के नवगछिया अनुमंडल अंतर्गत कांटीधार नवटोलिया, डीमहा, गोपालपुर नवगछिया के ग्रामीणों का गुस्सा अब सड़कों पर फूट पड़ा है। सड़क, पेयजल और बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर ग्रामीणों ने शनिवार को बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री बुलो मंडल के आवास के पास 21 दिवसीय आमरण अनशन शुरू कर दिया है। आंदोलन कर रहे ग्रामीणों का कहना है कि वर्ष 2007 से लगातार जनप्रतिनिधियों और प्रशासन से सड़क निर्माण की मांग की जा रही है, लेकिन आज तक हालात उस के तस बने हुए हैं। लोगों का आरोप है कि क्षेत्र से मंत्री बनने के बावजूद गांवों की तस्वीर नहीं बदली और आज भी लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अनशन स्थल



आमरण अनशन में भाग लेते ग्रामीण

पर लगाए गए बड़े पोस्टर में गांव की बदहाली को बेहद मार्मिक तरीके से दर्शाया गया है। पोस्टर में लिखा गया है कि सड़क नहीं रहने के कारण गर्भवती महिलाओं को खेत और कीचड़ भरे रास्तों से अस्पताल पहुंचाना पड़ता है। स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर गंगा नदी पार कर पढ़ाई करने जाते हैं। वहीं बीमार और घायल लोगों को समय पर इलाज नहीं मिलने से कई लोगों की जान तक चली गई। ग्रामीणों ने

कहा कि सड़क नहीं होने की वजह से शादी-विवाह जैसे सामाजिक कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। आजादी के इतने वर्षों बाद भी गांव मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। पेयजल संकट लगातार गहराता जा रहा है और लोगों की रोज भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पोस्टर में 'आजाद भारत का गुलाम गांव' लिखकर प्रशासन और जनप्रतिनिधियों पर तीखा हमला बोला गया है।

अब कृषि एप से मिलेंगी योजनाओं मौसम व खाद-बीज की जानकारी

AGENCY KATIHAR : बिहार के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब खेती से जुड़ी हर जरूरी जानकारी और सरकारी योजनाओं का फायदा सीधे मोबाइल पर मिलेगा। इसके लिए बिहार सरकार के कृषि विभाग ने 'बिहार कृषि एप' नाम से आधिकारिक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि इस ऐप का मकसद किसानों को डिजिटल रूप से मजबूत बनाना और आधुनिक खेती की जानकारी एक क्लिक पर देना है। अब किसानों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इस ऐप से किसान घर बैठे ही राज्य सरकार की सभी कृषि योजनाओं के लिए आवेदन कर सकेंगे और अपने आवेदन की स्थिति भी देख सकेंगे। आसपास



के केंद्रों पर यूरिया, डीएपी जैसे उर्वरक और उन्नत किस्म के बीज की उपलब्धता की समय पर जानकारी मिल जाएगी। खेती की सही योजना बनाने के लिए सटीक मौसम का हाल भी ऐप पर मिलेगा। किसान ऐप के जरिए अपना पंजीकरण भी करा सकते हैं। बीज अनुदान, कृषि यांत्रिकरण जैसी योजनाओं में ऑनलाइन आवेदन की सुविधा है। साथ ही खेती से जुड़ी किसी भी समस्या की शिकायत दर्ज कर समाधान पाया जा सकता है।

कार्यक्रम

550 सीसीटीवी व ड्रोन से की जाएगी निगरानी

आज से शुरू हो रहा राजगीर का विश्व प्रसिद्ध मलमास मेला

AGENCY NALANDA : बिहार में नालंदा जिले के राजगीर में आयोजित होने वाले विश्व प्रसिद्ध राजकीय मलमास मेला को लेकर नालंदा जिला प्रशासन ने तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। 17 मई यानी रविवार से शुरू हो रहे इस धार्मिक एवं सांस्कृतिक महा आयोजन को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय और सज्ज नजर आ रहा है। प्रशासन ने इसके लिए 550 सीसीटीवी व ड्रोन की व्यवस्था की है जो 24 घंटे निगरानी करेगी। इसी क्रम में शनिवार को नालंदा के जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने राजगीर पहुंचकर मेला क्षेत्र का व्यापक स्थलीय निरीक्षण किया तथा विभिन्न विभागों द्वारा की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। निरीक्षण



मेला स्थल का निरीक्षण करते जिलाधिकारी कुंदन कुमार व अन्य

के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण, यातायात, चिकित्सा, पेयजल, स्वच्छता, अग्निशमन, आपदा प्रबंधन और संचार व्यवस्था सहित तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए

कि मलमास मेला के दौरान श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह मेला नालंदा जिले की धार्मिक एवं सांस्कृतिक पहचान है और प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा तथा सुगम आवागमन

सुनिश्चित करना है। इसके लिए सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर कार्य किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान प्रशासन द्वारा आपदा प्रबंधन एवं आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का भी आयोजन किया गया। इस दौरान भगदड़, आग लगने, जल

दुर्घटना और अन्य संभावित आपदाओं से निपटने की तैयारी का व्यवहारिक प्रदर्शन चाया गया। मॉक ड्रिल में पुलिस बल, आपदा मित्र, अग्निशमन दल तथा स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने संयुक्त रूप से भाग लिया। जिलाधिकारी ने राहत एवं बचाव दलों को पूरी सतर्कता और तत्परता के साथ कार्य करने का निर्देश दिया।प्रशासन के अनुसार मलमास मेला की शुरूआत 17 मई 2026 को कुंड परिसर में ध्वजारोहण के साथ होगी। मेला 15 जून 2026 तक चलेगा। इस दौरान देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु राजगीर पहुंचेंगे और ब्रह्मकुंड में आस्था की डुबकी लगाएंगे। नेपाल, श्रीलंका समेत कई देशों से भी पर्यटक और श्रद्धालुओं के आने की संभावना है।

सरकार और देश में अंतर करना आवश्यक

लोकतंत्र की सबसे बुनियादी सच्चाइयों में से एक यह है कि देश और सरकार एक ही इकाई नहीं होते। यह फर्क केवल सैद्धांतिक नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक स्वास्थ्य का मूल आधार है। देश एक जीवंत, बहुस्तरीय और निरंतर विकसित होने वाली सामूहिक चेतना है और उसकी विविधताओं, संघर्षों, इतिहास, आकांक्षाओं और भविष्य का समुच्चय होता है। इसके विपरीत, सरकार एक अस्थायी व्यवस्था है, जिसे जनता समय-समय पर चुनती है। सरकारें आती-जाती रहती हैं, पर देश बना रहता है। इस सरल-सी प्रतीत होने वाली सच्चाई को धुंधला करना, लोकतंत्र की आत्मा को कमजोर करना है। समस्या तब उत्पन्न होती है, जब सत्ताधारी दल अपने राजनीतिक हितों को राष्ट्रहित के रूप में प्रस्तुत करने लगता है। यह प्रवृत्ति नई नहीं है, लेकिन आज के दौर में इसका स्वर अधिक मुखर और आक्रामक हो गया है। सरकार की आलोचना को देश की आलोचना के रूप में चित्रित करना, असहमति को राष्ट्रद्रोह के साथ जोड़ देना और किसी एक नेता की छवि को राष्ट्र की गरिमा के साथ मिला देना, ये सभी प्रवृत्तियाँ लोकतांत्रिक विमर्श को सीमित करने के औजार हैं। इससे नागरिकों पर दबाव पैदा होता है कि वे सवाल उठाने से बचें अन्यथा उन्हें देश-विरोधी ठहरा दिया जाएगा। यह माहौल लोकतंत्र की मूल भावना-स्वतंत्र विचार और बहस के सर्वथा प्रतिकूल है। किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र में आलोचना केवल एक अधिकार नहीं, बल्कि नागरिकों का कर्तव्य भी होती है। सरकार की नीतियों, निर्णयों और कार्यशैली पर सवाल उठाना, उनका विश्लेषण करना और आवश्यकतानुसार उनका विरोध करना सक्रिय नागरिकता के अनिवार्य तत्व हैं। यदि यह प्रक्रिया कमजोर पड़ती है, तो सत्ता का केंद्रीकरण बढ़ता है और जवाबदेही कम होती जाती है। जब-जब सरकार और राष्ट्र को एक मान लिया गया, तब-तब लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर हुईं, नागरिक अधिकारों पर अघात हुआ और तानाशाही प्रवृत्तियां पनपीं। किसी भी उच्च पदस्थ नेता की गरिमा और प्रतिष्ठा निस्संदेह महत्वपूर्ण होती है, लेकिन उसे राष्ट्र की गरिमा का पर्याय बना देना एक खतरनाक सरलीकरण है। राष्ट्र की प्रतिष्ठा किसी एक व्यक्ति को छवि पर नहीं, बल्कि उसके संस्थानों की मजबूती, नागरिकों की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की निष्पक्षता और समाज की समावेशी संरचना पर निर्भर करती है। जब हम किसी नेता की आलोचना को राष्ट्र के अपमान के रूप में देखने लगते हैं, तो हम अनजाने में लोकतंत्र के उस संतुलन को बिगाड़ देते हैं, जो संस्थाओं और व्यक्तियों के बीच स्थापित होना चाहिए। यह याद रखना प्रासंगिक है कि लोकतंत्र में संस्थाएं व्यक्तियों से बड़ी होती हैं। व्यक्ति-पूजा का यह चलन धीरे-धीरे संस्थागत ढांचे को कमजोर करता है और लोकतंत्र को एक व्यक्ति-केंद्रित व्यवस्था में बदलने का खतरा पैदा करता है। सत्ताधारी दल का हित और राष्ट्रहित भी हमेशा एक जैसे नहीं होते। हर दल स्वाभाविक रूप से अपने विस्तार, प्रभाव और चुनावी सफलता के लिए काम करता है और यह लोकतांत्रिक राजनीति का हिस्सा है, लेकिन जब इन हितों को राष्ट्रहित के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और विरोध की आवाजों को दबाने का प्रयास होता है, तब समस्या पैदा होती है। इससे नीति-निर्माण में विविध दृष्टिकोणों की गुंजाइश कम हो जाती है और निर्णय एकतरफा हो सकते हैं। लोकतंत्र का सार ही यह है कि विभिन्न विचारों के बीच संवाद हो और उसी से नीतियों का निर्माण हो। इस बहस में सबसे केंद्रीय भूमिका नागरिक की है। लोकतंत्र में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। सवाल पृष्ठना, जाचकाजी जुटाना, नीतियों का मूल्यांकन करना और अपनी स्वतंत्र राय बनाना, ये सभी लोकतांत्रिक नागरिकता के आवश्यक तत्व हैं। यदि नागरिक इस जिम्मेदारी से पीछे हटते हैं, तो सत्ता का असंतुलन बढ़ता है और लोकतंत्र कमजोर पड़ने लगता है। यह भी समझना जरूरी है कि आलोचना का अर्थ विरोध या नकारात्मकता नहीं होता। रचनात्मक आलोचना वह प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से नीतियों में सुधार होता है और शासन अधिक प्रभावी बनता है। एक परिपक्व लोकतंत्र में सरकार आलोचना को अवसर के रूप में देखती है, न कि खतरे के रूप में, लेकिन जब आलोचना की ही शत्रुता के रूप में देखा जाने लगे, तो यह लोकतांत्रिक अमुरक्षा का संकेत है। आज आवश्यकता इसकी है कि हम देश और सरकार के बीच इस अंतर को स्पष्ट रूप से समझें और बनाए रखें। हमें यह स्वीकार करना होगा कि सरकारें अस्थायी हैं, लेकिन देश स्थायी है। इसलिए हमारी सर्वोपरि निष्ठा किसी दल या व्यक्ति के प्रति नहीं, बल्कि उन मूल्यों के प्रति होनी चाहिए, जो इस देश को परिभाषित करते हैं- लोकतंत्र, न्याय, सामानता, संप्रभुता और स्वतंत्रता। एक सशक्त लोकतंत्र वही है, जहां नागरिक निर्भीक होकर सवाल पूछ सकें, जहां असहमति को सम्मान मिले और जहां सरकारें स्वयं को जनता के प्रति जवाबदेह मानें। देश और सरकार के बीच की इस आवश्यक दूरी को बनाए रखना ही लोकतंत्र की सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी है। यदि हम इस अंतर को भूल जाते हैं, तो हम न केवल अपनी नागरिक जिम्मेदारी से विमुख होते हैं, बल्कि उस लोकतांत्रिक आत्मा को भी कमजोर कर देते हैं, जिसने हमें एक राष्ट्र के रूप में एकजुट रखा है।

Social Media Corner

सब के हक में...

सिक्किम राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अपनी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पर्यावरण संरक्षण के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ, सिक्किम राष्ट्र के लिए सतत विकास का एक आदर्श है। सिक्किम के लोग अपने सौंदर्य, सादगी और सद्भाव की भावना के लिए जाने जाते हैं। राज्य और यहां की जनता की समृद्धि निरंतर बनी रहे।

(राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 'एक्स' पर पोस्ट)

अली फलिह काज़िम अल-जैदी को इराक के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने पर हार्दिक बधाई। भारत इराक के साथ अपने दीर्घकालिक और मैत्रीपूर्ण संबंधों को अत्यंत महत्व देता है और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। मैं उन्हें अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और दोनों देशों की साझा प्रगति और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की आशा करता हूँ।

(प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 'एक्स' पर पोस्ट)

वट सावित्री व्रत की सभी माताओं-बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं और जोहार। वट सावित्री व्रत केवल परंपरा का पर्व नहीं, बल्कि नारी शक्ति और अटूट संकल्प का प्रतीक है। परिवार और समाज की मजबूती में आधी आबादी की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। आइए, इस पर्व पर हम नारी सम्मान, समान अधिकार और पारिवारिक मूल्यों की ओर सशक्त बनाने का संकल्प लें। सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य बना रहे, यही कामना करता हूँ।

(हेमंत सोबन का 'एक्स' पर पोस्ट)

ANALYSIS



हृदयनारायण दीक्षित

इंटरनेट ने लाखों-करोड़ों सूचनाएं भर दी हैं। किसे छोड़ें, किसे पढ़ें, क्या शास्त्र पढ़ें। पढ़ें तो विवेचन विश्लेषण कैसे करें। जानने के लिए सोचना जरूरी है और सोचने के पहले ठीक से देखना भी। देखने की एक दृष्टि वैदिक पूर्वजों ने दी है। बाद के इतिहास और दर्शन में प्रायः उसी विवेक को आधार बनाया गया है। इस समझ को प्राप्त करने का दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ है ऋग्वेद। भारत के लोगों ने ऋग्वेद की रचना के पहले ही वैज्ञानिक चिंतन प्रारंभ कर दिया था। ऋग्वेद में इसी सोच-विचार के दर्शन हैं। चिंतन की यह दृष्टि निर्णयात्मक नहीं है। दर्शन और विज्ञान निर्णयात्मक नहीं होते। जहां तक जान लिया, वही रुक जाना उचित नहीं होता। सामान्य धारणा है कि विश्व किसी शक्ति द्वारा बनाया गया है। सृष्टि निर्माण विश्वकर्म है। सृष्टि निर्माता को विश्वकर्मा कहा गया है। ऋग्वेद के एक दार्शनिक सूक्त (10.81) के देवता विश्वकर्मा हैं। ऋषि पूछते हैं सृष्टि निर्माण के पहले वे कहाँ पर बैठे। प्रश्न उचित है। जब पृथ्वी, आकाश आदि थे ही नहीं तो विश्वकर्मा ने कहाँ बैठकर यह सृजन कर्म पूरा किया। विश्वकर्मा ने कहाँ बैठकर यह सृजन कर्म पूरा किया। पूछते हैं कि सृष्टि निर्माण का मूल द्रव्य क्या था। वह वन, वृक्ष कौन-सा था, जिससे विश्वकर्मा ने सामग्री ली और विराट विश्व बनाया।

हम सब सोचते हैं। अनेक प्रश्न उठते हैं। प्रश्न स्वयं को जानने का भी है। संसार और स्वयं का बोध जरूरी है। प्रश्न बड़ा है- कैसे जानें इस असीम संसार को। समझ छोटी अति अल्प और संसार बड़ा। प्रश्न और भी हैं। जैसे सृष्टि क्या है। सृष्टि का कोई निर्माता भी है क्या। यह सृष्टि नहीं थी तो क्या था। जो था, वह क्या था। क्या शून्य था। क्या सृष्टि ऊर्जा का खेल है। पृथ्वी जल, अग्नि और आकाश प्रत्यक्ष है। इनका सारभूत क्या है। सूर्य चंद्र और तारागण कहां से प्रकाश पाते हैं। सृष्टि निर्माण का आदि तत्व क्या है। कोई परमतत्व है क्या। क्या एक तत्व से ही यह सृष्टि बनी या सबका साझा प्रयास यह सृष्टि है। सृष्टि और हमारे सम्बंध क्या हैं। आखिरकार अस्तित्व को कैसे जानें, कैसे शांत करें जिज्ञासा को। कठिनाई दूसरी भी है- जितना देखते हैं, उतने का सार तत्व कैसे ग्रहण करें। हमारी जीवन दृष्टि क्या हो। इंटरनेट ने लाखों-करोड़ों सूचनाएं भर दी हैं। किसे छोड़ें, किसे पढ़ें, क्या शास्त्र पढ़ें। पढ़ें तो विवेचन विश्लेषण कैसे करें। जानने के लिए सोचना जरूरी है और सोचने के पहले ठीक से देखना भी। देखने की एक दृष्टि वैदिक पूर्वजों ने दी है। बाद के इतिहास और दर्शन में प्रायः उसी विवेक को आधार बनाया गया है। इस समझ को प्राप्त करने का दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ है ऋग्वेद। भारत के लोगों ने ऋग्वेद की रचना के पहले ही वैज्ञानिक चिंतन प्रारंभ कर दिया था। ऋग्वेद में इसी सोच-विचार के दर्शन हैं। चिंतन की यह दृष्टि निर्णयात्मक नहीं है। दर्शन और विज्ञान निर्णयात्मक नहीं होते। जहां तक जान लिया, वहीं रुक जाना उचित नहीं होता। सामान्य धारणा है कि विश्व किसी शक्ति द्वारा बनाया गया है। सृष्टि निर्माण विश्वकर्म है। सृष्टि निर्माता को विश्वकर्मा कहा गया है। ऋग्वेद के एक दार्शनिक सूक्त (10.81) के देवता विश्वकर्मा हैं। ऋषि पूछते हैं सृष्टि निर्माण के पहले वे कहाँ पर बैठे। प्रश्न उचित है। जब पृथ्वी, आकाश आदि थे ही नहीं तो विश्वकर्मा ने कहाँ बैठकर यह सृजन कर्म पूरा किया। विश्वकर्मा ने कहाँ बैठकर यह सृजन कर्म पूरा किया। पूछते हैं कि सृष्टि निर्माण का मूल द्रव्य क्या था। वह वन, वृक्ष कौन-सा था, जिससे विश्वकर्मा ने सामग्री ली और विराट विश्व बनाया। यह सब मनीषी लोग जानने का प्रयास करें। स्तुति है कि वे विश्वकर्मा मित्र भाव से हमें ज्ञान दें। ऋग्वेद के एक ऋषि देवताओं के



भी पहले का विचार करते हैं कि देवताओं के पहले युग समय में अस्त से सत् का जन्म हुआ। (10.72) यह युग विचारणीय है। तब देवता भी नहीं हैं लेकिन समय है। ऋग्वेद में सत् का अर्थ व्यक्त है और अस्त का अव्यक्त। नासदीय सूक्त (10.129) में प्रकृति सृष्टि के संबंध में और भी गहन चिन्तन है तब न सत् था और न अस्त। आकाश से परे भी कुछ नहीं था-नो व्योमा परो यत। अंधकार था। यहां अंधकार प्रकाश का अभाव नहीं है। अंधकार अस्तित्व है। इसी तरह एक और महत्वपूर्ण अस्तित्व वह एक था। ऋषि के अनुसार वह एक-तत् एक अपनी शक्ति के दम पर वायुहीन दशा में भी प्राण ले रहा था। ऋग्वेद का वह एक सृष्टि के पहले भी है। उस समय जल भी है-अप्रकेत सलिल। फिर काम उत्पन्न हुआ। इसके बाद प्रकाश की दीप्ति चारों ओर फैल गई। फिर विसृष्टि हुई। फिर कहते हैं क्या पता ऊंचे आकाश में बैठा सृष्टि का अध्यक्ष सृष्टि रचना की बात जानता है या वह भी न जानता। यह विवरण रोमांचक है। यहां शुद्ध वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया गया है। क्या अंधकार होता है या प्रकाश के अभाव का नाम ही अंधकार है। अंधकार सृष्टि के पूर्व भी है। संभवतः आकाश या प्रकाश का सूक्ष्म रूप। वह एक बिना वायु ही प्राण ले रहा था। क्या प्राण का विकास वायु हो सकती है। काम का जन्म भी सृष्टि के साथ हुआ। यह ताप या अग्नि ऊर्जा का सूक्ष्म रूप हो सकता है। सबसे अंत में है- विसृष्टि। विसृष्टि-सृष्टि है, इसमें पृथ्वी भी है। भारतीय चिंतन में आकाश सूक्ष्मतम है।

आकाश से वायु, वायु के बाद अग्नि, इसके बाद जल और फिर पृथ्वी। सृष्टि का विकास किसी एक तत्व से हुआ है। यहां आकाश प्रमुख तत्व है। कपिल के सांख्य दर्शन में आकाश प्राचीनतम है। भारतीय चिन्तन के पांच महाभूतों में से प्रथम। भारतीय दर्शन में असीम आकाश का गुण शब्द है। आकाश का अस्तित्व है। छांदोग्य उपनिषद् के अनुसार सभी भूत आकाश से पैदा होते हैं और आकाश में ही विलीन हो जाते हैं। आकाश से आना और आकाश में ही लौटना विचारणीय है। ऋग्वेद में ठीक ही आकाश पिता है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में पुरुष का वर्णन है। यह पुरुष देश-काल की सीमा का अतिक्रमण करता है। उसका सिर आकाश है और सहस्रशीर्षा है। इस पुरुष के प्राण का विस्तार वायु है। पुरुष समूचे अस्तित्व को घेरता है। दश अंगुल इसके बाहर भी है। संपूर्ण संसार इसका एक चरण है। इसके तीन चरण अन्य लोगों में हैं। यहां जो कुछ चेतन या अचेतन मनुष्य, पशु, कीट, पक्षि, नदी, समुद्र या वन है। पुरुष सब में व्याप्त है। यहां तक हुआ दिव या दिशा का अतिक्रमण। अब काल। बताते हैं कि यह पुरुष ही सब कुछ है-पुरुष एवेदं सर्व। जो भूतकाल में हो गया है और जो आगे भविष्य में होगा वह सब पुरुष ही है-यद् भूतं यच्च भव्यं। ऋग्वेद के एक देवता हैं अदिति। अदिति भी सर्वस्व धारण करते हैं। वह अंतरिक्ष है, पृथ्वी हैं। पिता-माता और पुत्र हैं। वे पांच जन हैं। अब तक जो हो चुका है और जो भविष्य में होगा वह सब अदिति ही हैं। समूचे अस्तित्व

को एक देखना और स्वयं को उसी का भाग जानना भारतीय चिंतन की मूल भूमि है। यहां अस्तित्व या सृष्टि का कोई निर्माता नहीं। प्रकृति के गोचर प्रपंच गतिशील है। सम्यक गति से प्रगति होती है। प्रकृति का वैज्ञानिक अध्ययन भी मूलतः गति का ही अध्ययन है। प्राचीन यूनानी दार्शनिक थेल्स (लगभग 500 ईसा पूर्व) जल को सृष्टि का आदि तत्व मानते थे। इसके हजारों वर्ष पहले ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में अप्रकेत सलिल-जल है। जल से सृष्टि का जन्म हुआ तो जल को माता कहना ही चाहिए। ऋग्वेद में जल को बहुवचन रूप में आपः मातरम्-जल माताएं कहा गया है। स्थावर जंगम को जन्म देने वाली यही जल माताएं ही हैं। थेल्स जल संबंधी चिन्तन ऋग्वेद के संगत है। वैसे ऋग्वेद में अनेक विचार हैं। एक यूनानी दार्शनिक अर्नक्सिमेनेस वायु को सृष्टि का मूल तत्व बताते थे। ऋग्वेद (10.168) में ऋतावा-नियम वायु है। यहां वायु जलों के मित्र कहें गए हैं-अपां सखां। ऋग्वेद के जल और वायु आदि तत्व इसी रूप में उपनिषदों में भी हैं। हिराक्लिटस अग्नि को प्रधान तत्व जानते हैं। अग्नि ऋग्वेद के प्रधान देवता हैं। अग्नि सब जगह हैं। वे जलों में हैं। मनुष्य के भीतर हैं। यत्र-तत्र सर्वत्र हैं। कटोपनिषद् में यम ने नविकेता को अग्नि विज्ञान समझाया था। यहां अग्नि ही प्रत्येक जगह उपस्थित होकर रूप-रूप प्रतिरूप होते हैं-अग्निवथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो वधूवाः। जानने और गहराई से देखने-समझने के एकात्म चिंतन की जन्मभूमि भारत ही है।

बंगाल में परिवर्तन के साथ पुनर्जागरण

हे नूतन, देखा दिक आर-बार, जन्मेरो प्रथम शुभोखोन। इसका अर्थ है-हे नवीन, एक बार फिर से सामने आओ, ठीक उसी तरह जैसे जन्म के समय वह पहला शुभ क्षण आया था। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की यह पंक्तियां केवल एक कविता का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि समय-समय पर स्वतःस्फूर्त और नवीन होने वाली बंगाल के आत्मा का आह्वान भी हैं। गुरुदेव भली-भांति समझते थे कि बंगाल समय के साथ केवल बदलता नहीं है, बल्कि वह बार-बार बेहतर और नए रूप में पल्लवित होता है। गुरुदेव की जयंती पर गाई जाने वाली यह कविता नवजागरण और नवचेतना की प्रतीक है। यह एक सुखद संयोग है कि टैगोर की 165वीं जयंती से कुछ दिन पहले ही बंगाल कई दशकों के बाद नवजागरण का साक्षी बना। भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी के लिए यह चुनाव कभी सिर्फ एक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा नहीं था। यह चुनाव इस महान भूमि के खोए हुए गौरव को पुनर्स्थापित करने का एक अवसर था-एक ऐसा सभ्यतागत

आह्वान, जो चुनावी समीकरणों और गणनाओं से कहीं ऊपर है। आज जब बंगाल की चेतना और गौरव का अरुणोदय हो रहा है, तो यह समझने की आवश्यकता है कि बंगाल क्या है और उसकी चेतना का पुनर्जागरण किसे कहा जा सकता है। बंगाल सामाजिक चेतना का केंद्र होने से पहले ज्ञान और आध्यात्मिकता की पवित्र भूमि थी। 15वीं शताब्दी में नवद्वीप के गंगा तट पर एक युवा संन्यासी निमाई ने अपने कीर्तन का माध्यम से समाज को नई दिशा दी। उस युवा संन्यासी को हम संत चैतन्य महाप्रभु के नाम से जानते हैं। उनके द्वारा दिखाया गया भक्ति मार्ग आध्यात्मिक शांति प्राप्त करने के साथ-साथ सामाजिक समरसता को अभिमान भी था। उनके द्वारा प्रवाहित वैष्णव परंपरा ने समाज में करुणा, समावेशिता, समता और सद्भावना को बल दिया। यही चेतना बाउल परंपरा में भी दिखाई दी। बाउल परंपरा के फकीरों की पहचान जाति, पंथ या कोई ग्रंथ नहीं, बल्कि मानवता की भावना थी। बाउल परंपरा के सबसे महान प्रवर्तक

लालन फकीर थे। वे किस संप्रदाय से थे, यह कभी महत्वपूर्ण नहीं रहा। उन्होंने हिंदू समाज में प्रचलित जाति व्यवस्था का भी विरोध किया तथा मुस्लिम समाज में होने वाले भेदभाव के खिलाफ भी आवाज उठाई। वे बंगाल की उस सांस्कृतिक चेतना के प्रतीक थे, जिसमें सहिष्णुता और सह-अस्तित्व का भाव समाहित था। विगत तीन शताब्दियों में बंगाल और यहां के लोगों ने केवल भारत के सामाजिक नवजागरण आंदोलन के भाग ही नहीं लिया, बल्कि उसका नेतृत्व भी किया। राजा राममोहन राय ने लोगों को आत्मबोध कराकर समाज को भीतर से सुधारने का मार्ग चुना। सती प्रथा जैसी अमानवीय कुरीति के विरुद्ध उनका संघर्ष केवल समाज सुधार से जुड़ा आंदोलन नहीं था, बल्कि भारतीय आत्मा को पुनर्जीवित करने का एक तप था। इसी तरह ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने शिक्षा को नारी शक्ति के उथान, सशक्तीकरण और मुक्ति का साधन बनाया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम जैसा अमर मंत्र राष्ट्र को दिया। इस गीत ने

ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ने में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को बल दिया और सदियों से सोए हुए देश को जगा दिया। यह गीत आज भी भारत के लोगों के अंतरात्मा का स्वर है। भारत की पहली महिला चिकित्सक डॉ. कादंबिनी गांगुली ने सभी को और विशेषकर महिलाओं को प्रेरित किया। बंगाल की ही धरती पर जन्मे प्रखर राष्ट्रवादी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। संभवतः बंगाल की धरती ने जितनी विलक्षण प्रतिभाओं और महान लोगों को जन्म दिया, उनमें सबसे देदीप्यमान और प्रबुद्ध स्वामी विवेकानंद को कहा जा सकता है। शिकागो में दिया गया उनका भाषण इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। उन्होंने विश्व को वेदांत और भारत के महान सभ्यतागत मूल्यों से परिचित कराया। दुर्भाग्यवश लंबे समय तक बंगाल के कुछ बुद्धिजीवियों और राजनीतिक वर्गों ने अपनी ही सांस्कृतिक विरासत को बोझ समझा और उसे हेय दृष्टि से

उपेक्षित और जीर्ण-शीर्ण हो चुके इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण तो है ही, साथ ही उन घाटों को पुनर्जीवित करना भी है, जहां चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन ने लोगों को भाव-विभोर किया था। इसका अर्थ उन शैक्षणिक संस्थानों को सशक्त करना भी है, जिनका स्वप्न ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने देखा था। इसका अर्थ आदिवासी भाइयों-बहनों का ग्राम-सम्मान और अवसर देना और उपेक्षा झेल रहे पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना भी है। पिछले कुछ दशकों में भय और कुशासन के कारण ऐसा प्रतीत होने लगा था मानो बंगाल का स्वर्णिम युग बीत चुका हो, किंतु आज बंगाल एक बार फिर नए आत्मविश्वास और नई ऊर्जा के साथ समृद्धि एवं शांति से भरे नए युग में प्रवेश कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में बनी पहली भाजपा सरकार गुरुदेव के द्वारा वर्णित नूतन भावना के साथ सेवा का संकल्प लेकर आगे बढ़ेगी और बंगाल की प्रीतिष्ठ और समृद्धि के साथ राज्य का सांस्कृतिक गौरव बढ़ाने के लिए कार्य करेगी।

वाद निस्तारण को लेकर राजस्थान की पहल

देश में राजस्व विवादों से संबंधित लाखों की संख्या में प्रकरण राजस्व न्यायालयों में निस्तारण के अभाव में पेंडिंग पड़े हैं। इनमें से हजारों की संख्या में ऐसे प्रकरण भी मिल जाएंगे जो तीस साल से भी अधिक समय से निर्णय के इंतजार में हैं। राजस्व न्यायालयों में विवाद के ये प्रकरण केवल राजस्व रेकार्ड में संशोधन कर सुधार के हैं, क्योंकि मालिकाना हक तय करने के मामले तो सिविल कोर्ट द्वारा निर्णित किये जाते हैं। रेवेन्यू कोर्ट में मुख्यतः म्यूटेशन, भूमि का बंटवारा, जमीन के सीमांकन, भूमि पर अतिक्रमण, दस्तावेजों में सुधार, लगान या इस तरह के विवाद या फिर पट्टेदारी के विवाद से संबंधित विवाद निस्तारण के लिए आते हैं। आरसीसीएमएस जैसी कम्प्यूटीरकृत व्यवस्था होने के बावजूद इसमें कोई खास सुधार नहीं देखा जा रहा है। होता यह है कि इस तरह के विवादों या प्रकरणों के निर्णित होने में भी पीढ़ी दर पीढ़ी निर्णय के लिए तारीख दर तारीख न्यायालयों के चक्कर लगाते रहते हैं। यह अपने आप में गंभीर समस्या है पर इसका निराकरण सरकारों की इच्छा शक्ति और व्यवस्था में सुधार से आसानी से किया जा सकता है। खास बात यह कि इस तरह के लाखों की संख्या में विवाद निर्णय के अभाव में पेंडिंग पड़े हैं। राजस्थान की सरकार ने लॉबिड प्रकरणों को लेकर महत्वपूर्ण पहल की है। अब पीठासीन अधिकारियों को प्राप्त: 10 बजे से 2 बजे तक

नियमित सुनवाई करने के साथ ही प्रकरणों के निष्पादन की टाइम लाइन और मॉनिटरिंग व्यवस्था को सुदृढ़ किया है। यह कोई अकेले राजस्थान का ही मुद्दा नहीं है अपितु सभी राज्यों में इस तरह के विचाराधीन प्रकरणों की संख्या बहुत चिंतीय स्थिति में है। गंभीरता को इसी से समझा जा सकता है और ऐसे भी उदाहरण देखने को मिलता है कि कई राजस्व न्यायालयों में तो सालभर में एक-एक केस का निस्तारण तक देखने को मिलता है। यह अपने आप में गंभीर होने के साथ कहीं-ना-कहीं हमारी व्यवस्था के लिए भी चुनौती से कम नहीं है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अनुसार, राजस्व न्यायालयों के सुदृढ़ीकरण और लॉबिड वादों का निस्तारण सरकार की प्राथमिकता है। अकेले राजस्थान की ही आंकड़ों में बात की जाए तो इस तरह के 6 लाख 72 हजार वाद रेवेन्यू न्यायालयों में विचाराधीन चल रहे हैं। इनमें से करीब 64 प्रतिशत 4.31 लाख के वाद उपखण्ड अधिकारी के न्यायालयों में निर्णयाधीन है। चिंतनीय यह है कि 6 हजार के करीब वाद तो ऐसे हैं जो 20 से 30 साल के बीच निर्णय के प्रतीक्षा में हैं। राजस्थान के प्रमुख सचिव राजस्व टी. रविकांत ने इस तरह के प्रकरणों को लेकर गंभीरता दिखाई और रिव्यू के बाद इस तरह की व्यवस्था चाक-चौबंद करने के निर्देश जारी कराने की पहल की है कि राजस्व न्यायालयों में विचाराधीन वादों की समयबद्ध नियमित सुनवाई हो, तारीखों पर

तारीखें नहीं दी जाएं और पक्ष-प्रतिपक्ष को समुचित अवसर देते हुए वादों का प्राथमिकता से निस्तारण किया जाए। प्रमुख सचिव राजस्व राजस्थान टी. रविकांत ने व्यवस्था में सुधार और संवेदनशील प्रशासन का परिचय देते हुए मुख्य सचिव राजस्थान वी. श्रीनिवास ने परिपत्र जारी कर आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी किये हैं। यह कोई राजस्थान की नहीं, अपितु इस तरह की पहल की सभी राज्य सरकारों द्वारा किया जाने की आवश्यकता है। राजस्व न्यायालयों में विचाराधीन वादों के निस्तारण में मुख्यतः तीन कारण सामने आते हैं। इनमें भी सबसे प्रमुख कारण संबंधित पटवायें, गिरदावर, तहसीलदार द्वारा मौका रिपोर्ट सालों तक प्रस्तुत नहीं करना देखा गया है। एक अन्य कारण राजस्व न्यायालयों से जुड़े कार्मिकों को न्यायिक प्रक्रिया के संबंध में प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक हो जाता है। आवश्यक न्यायिक प्रक्रिया की जानकारी के अभाव में भी देरी होती है। इसके अलावा एक अन्य कारण जो कि सर्वविदित है और वह है न्यायालय के नोटिस का तामील नहीं होना भी है। तामीली के अभाव में समय अधिक लग जाता है। इसके अलावा तारीख-पर-तारीख और लंबी तारीख देने की परंपरा भी वादों के निस्तारण की बड़ी बाधा है। राजस्थान का संघर्ष इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि इन कारणों को गंभीरता से लेते हुए स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं।

पुल बनाने की जरूरत

भारत में 25 अप्रैल को बिजली की सर्वोच्च मांग (पीक डिमांड) 256.1 गीगावाट तक पहुंच गई थी, जिसमें दोपहर के लोड के 21.5 फीसद की आपूर्ति सौर संयंत्रों ने की। यह अब तक सर्वाधिक है और इस बात का भी साफ संकेत है कि जब सूरज सिर के ऊपर होता है तो देश में स्थापित सौर क्षमता सचमुच काम कर सकती है। लेकिन, उसी दिन के पूरे 24 घंटे के खाता-बही से जो कहानी सामने आती है, वह सोचने पर मजबूर करती है। बीते 25 अप्रैल के पूरे दिन के हिसाब को देखें, तो सौर ऊर्जा का योगदान दैनिक उत्पादन का 10.8 फीसदी रहा और सूर्यास्त के बाद शाम की जरूरतों का महज 0.1 फीसद। भारत में स्थापित विद्युत क्षमता में सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी साल 2022 के 15 फीसद से तकरीबन दोगुनी होकर साल 2026 के शुरू में लगभग 28 फीसद पर पहुंच गई। हालाँकि, साल 2022 में भारत के सर्वोच्च मांग वाले दिन उत्पादन में सौर का हिस्सा लगभग 5.6 फीसदी था और यह बढ़कर अप्रैल के उत्पादन का 10.8 फीसदी ही हो पाया, यह मौजूदा वास्तविकताओं और क्या मुमकिन है के बीच बरकरार बड़े फासले का भी साफ संकेत है। मामला जहां अटक है वह पैनल, जमीन या महत्वाकांक्षा नहीं है, बल्कि बैट्रियों के जरिए उत्पादित इलेक्ट्रॉनों के विशाल भंडारों का इस्तेमाल कर पाने की अक्षमता है। दरअसल, बैटरी भंडारण की इतनी कमी है कि सौर बिजली के प्रचुर उत्पादक राज्यों को अपनी आपूर्ति रोकने के लिए कहा जा रहा है, अन्यथा इससे भारत के बिजली ग्रिड की स्थिरता को खतरा हो सकता है। साल 2025 में, भारत को मई के आखिर और दिसंबर के बीच सौर उत्पादन के 2.3 टेरावाट घंटों की कटौती करनी पड़ी, जो औसत मासिक सौर उत्पादन के 18 फीसदी के बराबर है। अकेले अक्टूबर महीने में 0.9 टेरावाट घंटों की बबादी हुई।

Heed warning bells sounded by sliding rupee

There are moments when a currency tells a story more honestly than official statements do. The Indian rupee is doing exactly that. It has lost more than 12 percent against the US dollar in 12 months and has been sliding relentlessly even though India’s macroeconomic fundamentals are not in obvious crisis territory. Growth is still respectable. Inflation is not runaway. The current account deficit, at least in headline terms, is manageable. Forex reserves remain robust. This is not 1991. But that is precisely why the rupee’s fall is worrying. If a currency weakens sharply despite decent growth and contained inflation, it is telling us that the problem lies elsewhere: in the balance of payments, capital flows, investor confidence, oil vulnerability and the structure of India’s external dependence.

India’s chief economic advisor has argued that the rupee’s depreciation is not justified by fundamentals. He points to strong growth, moderate inflation, low external debt and a manageable current account deficit. He also argues that global capital has been sucked into the artificial intelligence investment boom and dollar assets, leaving otherwise sound emerging markets under pressure.

That is a fair point. Exchange rates often reflect capital flows more than textbook fundamentals. But saying that the rupee is mispriced is not enough. A mispriced currency can still bankrupt balance sheets, raise import costs, hurt confidence and trigger defensive behaviour. Markets may be irrational for a long time, but countries must still pay their import bills in real dollars. The real danger is that India’s external account is no longer getting the capital cushion it once did. For decades, India has run a current account deficit, but financed it through capital inflows. That bargain is fraying. Net foreign direct investment has been falling for several years. Gross inflows may still look impressive, but repatriation and outbound FDI have reduced net FDI close to negligible levels. Besides, foreign portfolio investors have pulled out close to \$40 billion in the past two years. The outflow this year has been the worst in almost 15 years.

This is the heart of the matter. India’s current account deficit may be below 2 percent of GDP, but the capital account is weak. The balance of payments will be sharply negative this year. When the BoP turns negative, either the rupee weakens or the RBI sells dollars to defend it. Both are now happening. The oil shock makes this worse. The CEA has called the West Asia crisis a live “balance of payments stress test”, with direct consequences for inflation, the current account and the exchange rate. Almost half of India’s crude imports transit through or near the Strait of Hormuz. That means an oil shock is not merely a petrol pump problem. It is a macroeconomic problem. When oil prices spike, three things happen at once. First, the import bill rises and the current account worsens. Second, inflation creeps up because fuel enters transport, fertilisers, plastics, food distribution and almost every other supply chain. Third, the fiscal deficit worsens if the government tries to shield consumers through LPG, fertiliser or petroleum subsidies. If pump prices are not raised, oil marketing companies take the hit. If they are raised, consumers suffer. If subsidies absorb the shock, taxpayers suffer. In reality, the three groups overlap: the taxpayer, the consumer and the shareholder are often the same Indian household wearing different hats. There is no choice but to raise pump prices. Many prominent voices are sounding this chorus. Else the fiscal deficit worsens adding to macro stress.

New doctrines, old dangers

One year after Op Sindoor, India’s new normal faces Pakistan’s new abnormal — putting a fragile truce at risk

ON the anniversary of the 2025 summer skirmish with Pakistan, India can claim to have forged a credible new doctrine of counterterrorism and controlled escalation in a nuclear neighbourhood. The 88-hour conflict, triggered by the Pahalgam terror attack and carried out under Operation Sindoor, marked the culmination of a decade-long shift towards assured kinetic responses to cross-border terror and served as a stress test for the subcontinent’s nuclear architecture.

The conflict followed a now-familiar script. As in 2016 and 2019, India retaliated after a terrorist attack in Kashmir that it attributed to Pakistani state-backed actors. What set Sindoor apart was the depth and precision of the response. Nine terrorist base camps were struck on May 7, 2025. Three days later, India hit eleven Pakistani airfields after suppressing Pakistani air defences. India’s indigenous air-defence systems also proved highly effective against Pakistani drones and missiles. Over the past year, most global analysts reviewing satellite imagery and competing claims have concluded that the military advantage lay overwhelmingly with India — despite documented evidence of Chinese technical personnel operating Pakistani systems, a significant detail that drew too little international scrutiny.

India’s diplomacy secured broad acceptance of its right to defend itself against terrorism. Where it fell short was in the information battle. Television and social media often amplified jingoistic claims unsupported by facts, while the government was slow to present credible evidence to a global audience against a propaganda state flooding the zone with half-truths. That gap is now being addressed.

India’s five commandments

In July 2025, the Modi government codified its counterterror doctrine before Parliament in five explicit tenets: cross-border attacks will invite direct responses; terrorists and their state backers will be treated alike; talks and terror cannot go together, though talks about terror may still be possible; nuclear blackmail will not alter India’s calculus; and blood and water will not flow together. The last tenet carries particular weight. India placed the 1960 Indus Waters Treaty ‘in abeyance’, even though it had survived two full-scale wars and multiple crises. For policymakers, it was the last major non-kinetic lever available to deter terror. Suspending such a consequential treaty signalled that India’s tolerance for terrorism — whether sponsored from within or beyond its borders — had sharply diminished. In February 2026,



suspended the Indus Waters Treaty days before kinetic operations began, adding a third layer: no water for terror.

Each provocation has drawn a qualitatively higher response. India has built a visible cost architecture in which the price of future provocations is, in principle, known in advance. Whether that visibility deters or instead invites calibrated brinkmanship is now South Asia’s central strategic question.

The end of Operation Sindoor deserves equal attention. India entered the operation with defined political objectives, demonstrated overwhelming capability and disengaged on its own terms — before exhaustion or external pressure forced an off-ramp. In the fifth year of the Ukraine conflict and the third year of horizontal escalation in West Asia, Vladimir Putin, Benjamin Netanyahu and Donald Trump would do well to study

the Sindoor playbook.

Pakistan’s new abnormal

The sharpest escalation of the past year has been Asim Munir’s rise. He entered the spring of 2025 as perhaps the most vulnerable Pakistani army chief in a generation — presiding over a contracting economy, the jailing of a former prime minister and deep public resentment. He emerged from Sindoor dramatically stronger. Promoted to Field Marshal in May 2025, appointed Chief of Defence Forces in December and granted lifelong legal immunity under the 27th Constitutional Amendment, he now wields a degree of formal personal power without recent precedent in Pakistan.

Yet this political rebirth rests on structural weakness: Pakistan’s polycrisis of economic decline, security failures and political tension. Munir now accumulates roles — military supremo, chief economic planner, chief regional peacemaker — that in a functioning state would be distributed across accountable institutions. As Pakistan’s chief diplomat charged with brokering a deal to resolve the Iran crisis, Munir’s army claims he has skillfully made Pakistan relevant again to its three principal benefactors: the US, China and Saudi Arabia. On the anniversary of Operation Sindoor, he also cast himself as Pakistan’s chief spokesman, again claiming victory against India and defining Pakistan’s new posture as one of conventional strength, multi-domain operational capability and the ability to strike India ‘in depth’ with high-tech weaponry.

Unpeace equilibrium

There has been no Pahalgam-scale attack in the year since the May 10 ceasefire. That pause is real, but it should be read carefully. The incentives that reward controlled provocation from Pakistan remain intact. Munir’s political survival depends on maintaining calibrated tension with India — enough to justify the army’s primacy, but not enough yet to trigger another Sindoor.

South Asia has reached a new equilibrium: more stable on the surface, more dangerous underneath. Pakistan has a more powerful army chief, a temporarily suppressed terrorist infrastructure and a deepening fiscal hole. A hard state built on military dominance, without economic foundations or democratic legitimacy, is ultimately brittle. The danger of future conflict still lies within that weakness. What deserves debate now is a more creative approach to mitigating that risk and managing the next crisis, and a doctrine better suited to dealing with an abnormal neighbour.

Kerala breakthrough : Congress balances state & national interests

In choosing Satheesan, the party appears to have rewarded political performance over hierarchy

THE Congress seems to have got so used to losing elections that it struggles to be decisive after it actually wins. The remarkable victory in Kerala was the face-saver for the party in the recent Assembly elections. Yet, the Congress took no less than 10 days to appoint VD Satheesan as the chief minister. It’s true that the high command was spoilt for choice — experienced leaders such as KC Venugopal and Ramesh Chennithala were also in contention for the top post — but the inordinate delay in naming the CM exposed the Congress’ familiar struggle with internal consensus-building. In choosing Satheesan, the party appears to have rewarded political performance over hierarchy. Over the past five years, he emerged as one of Kerala’s most prominent Opposition voices, consistently challenging the Left government on corruption and misgovernance. His sharp legislative interventions and energetic campaigning helped revitalise the



Congress-led United Democratic Front (UDF) after its 2021 defeat. More importantly, he succeeded in

projecting a younger and more assertive image of the party in the southern state. Venugopal, who is close to Rahul Gandhi, has “humbly accepted” the top brass’ decision, which aims to balance the party’s state and national interests. His continued organisational role at the central level is vital for the Congress in view of the 2027-28 Assembly elections and the 2029 Lok Sabha polls. The party will expect Venugopal and Chennithala to provide tangible support to Satheesan, who has his work cut out. The new government must address youth unemployment (which prevails despite a high literacy rate), rising debt, infrastructure concerns and social welfare expectations, while maintaining unity among UDF allies. The Congress should make the most of this opportunity to assert its southern dominance through good governance.

Is India becoming one big exam centre

Educating a child has to be India’s goal, not testing whether she is capable of being educated.

This article is being penned as much in anguish as in hope. The anguish is nationwide and stems from the enormous distress and demoralisation that has affected a large segment of our youth whose hopes and expectations of success were dashed just a couple of days back when a “guess paper” linked to the NEET examination was leaked, and the exam subsequently cancelled. The torment that prospective examinees face is easy to understand but very hard to alleviate. After all, when someone decides to enrol for an exam, she invests an important part of the formative years of her life to the tortuous process of preparing for it. In addition, she incurs significant expenses for coaching as she knows that that is a key element to success. And what are the odds of her succeeding? Given that there were 22,750,11 candidates who were scheduled to take the NEET examination this year and only 1,29,000 MBBS seats, it follows that her chances of success were a mere 6 per cent. In other words, for every one hundred candidates, less than six would be selected. Imagine what goes on in the mind of a youngster who gambles so much of her intellectual and economic capital for so little?

By all accounts, a large number of the candidates were from the not so well-off segments of society. The anguish is exacerbated when you know that this is not the first time such a leak has happened — nor are they confined to the NEET examination alone. A cursory examination of the data related to the history of question paper leaks in India will disabuse the reader of any such notion. This brings us to a larger issue, which is that we are examining our students



AIIMS. Coaching centres are perceived as necessary gateways for enabling schoolchildren to succeed at the various entrance examinations that are being conducted by our worthy institutions of knowledge. The list of such examinations is countless; there’s NEET, of course, but also CUET and JEE, plus GATE and CAT. The day is not

far off when viewed from outer space India shall appear as one big exam centre. This business of inflicting one exam after another on young and impressionable minds flies in the face of the 2020 National Education Policy (NEP). The policy advocates a much more enlightened approach that advocates testing as means of enabling a student to gain knowledge and not for disabling the mind of the student.

To imbue a bit of fresh air into the discussion at hand, I would like to draw attention to an interesting experiment underway for about three years in Jammu and Kashmir.

In keeping with the spirit of the NEP 2020, several prominent universities in J&K have launched an innovative undergraduate degree programme formally known as the Design Your Degree Programme. The main features of this include, exposure to communication and analytical skills, alongside training in the use of data and IT. Learning happens largely through group-based project work. The blackboard plays a substantially diminished role. Extra-curricular and co-curricular activities carry academic credit, as does entrepreneurial activity. Students take part in activities such as riding on a train that gets converted to a College On Wheels, where they work on projects related to any aspect of the journey onboard and where the train halts. As students progress year by year, they begin to realise their yearnings and interests and specialise accordingly. They have the option of exiting after one year with a certificate that records the credit earned, after two years with a diploma, after three years with an undergraduate degree with specialisation of their choice, or after four years with an Honours degree which has a research

component. Testing happens in enlightened ways where project outcomes are presented and discussed in depth before credit is accorded. But to return to the NEET crisis, let me say here that all is not lost; simple, but powerful ways of re-imagining the NEET exam exist, especially if meticulous planning is paired with shrewd technology. What is puzzling isn’t primarily the issue of leaks, but rather our apparent powerlessness in halting the decay. Here is a foolproof way to fix the testing crisis. First, the National Testing Agency (NTA) should invest massively in building a meticulously curated question repository. Foolproof Internet connectivity at every test venue needs dependable power backups and high-speed, sturdy laser printers too. The NTA must develop a sophisticated algorithm capable of instantly generating a flawless question set via unpredictable randomisation. This set would be transmitted securely, in encrypted digital format, to all centres mere hours ahead of exam start time. Centres would then print copies just two hours prior. Every exam room must have clear-recording video surveillance of all proceedings. Papers can thus circulate securely without risk. Ideally, equipping candidates with solid desktops or laptops would allow emailing the paper directly at exam time, with typed responses submitted via secure software to a central grading hub. Alternatively, handwritten answers on paper remain viable. This serves as an initial blueprint to spark a brainstorming drive toward a tamper-proof system that restores candidate confidence. What I have proposed here is not NEET-specific. It is a simple model for conducting any exam without the fear of leakages. Testing is only supposed to be a medium for learning, it cannot be a substitute for it. Educating a child has to be India’s goal, not testing whether she is capable of being educated.

Govt revises petrol export tax, cuts diesel, ATF duties

New Delhi,.(Agency)
The government has revised export taxes on petroleum products, imposing a special additional excise duty (SAED) of Rs 3 per litre on petrol exports while reducing the duty on diesel to Rs 16.5 per litre, effective from Saturday.
The notification by the Ministry of Finance stated that the entry of Rs 3 per litre shall be substituted for petrol exports, while diesel has been revised to Rs 16.5 per litre.It further said the road and infrastructure cess has been reduced to zero on petrol and diesel exports.The fresh SAED levy on petrol exports marks the first such duty since the outbreak of the West Asia conflict.
While export duties on diesel and ATF have been reduced from higher levels after a series of revisions in recent months.Earlier, export duty on diesel was revised multiple times. It was first set at Rs 21.50 per litre on March 26, then raised to Rs 55.5 per litre on April 11. Later, it was cut to Rs 23 per litre on April 30, and has now been further reduced to Rs 16.5 per litre.Similarly, aviation turbine fuel (ATF) followed a similar pattern. The duty was first Rs 29.5 per litre, then increased to Rs 42 per litre. It was later reduced to Rs 33 per litre and has now been brought down to Rs 16 per litre.The windfall tax framework was introduced to ensure adequate domestic fuel availability and curb exports amid volatile global oil markets triggered by the West Asia crisis.Geopolitical tensions remain elevated after the United States and Iran failed to reach a peace agreement, with US President Donald Trump rejecting Iran’s proposal, saying: “I don’t like it — TOTALLY UNACCEPTABLE.”

NPS annuity exit rules eased for retirees facing financial emergency: Know the details

Kolkata .(Agency)
One of the reasons why NPS, or National Pension System, is yet to enlist the desired number of subscribers is often cited to be the rigidity inherent in the structure. PFRDA, or the Pension Fund Regulatory and Development Authority, which regulates the system, has eased one of the rigid rules of annuity. The PFRDA’s new rules will make it easier for retirees could find themselves stuck with older annuity contracts. On May 14, PFRDA issued a circular which stipulated that annuity service providers can now permit surrender of annuity policies in select cases. These are specifically instances where the annuitant, or a family member of the annuitant, is critically ill and needs funds quickly on an emergency basis. There is a second category too — NPS subscribers for whom the annuity policy was issued before October 24, 2024 and already carried an explicit surrender clause. While the earlier system almost debarred exiting an annuity, the new PFRDA rule can be viewed as a significant easing of the rigidity.
The significance for NPS subscribers
Under the NPS rules, subscribers are required to retain at least 40% of their retirement corpus to buy annuity. This other portion — 100% minus whatever is retained for annuity — is used for providing monthly pension after retirement. These rules governing the annuity portions are extremely rigid and illiquid. The NPS subscribers could not exit annuities earlier. Needless to say, it was of inconvenience to many NPS subscribers who just couldn’t take out the money irrespective of how severe the emergency was.
What changed after the 2024 circular
PFRDA had earlier tightened annuity rules. In October 2024 a circular barred annuity service providers from allowing surrender or cancellation of annuities. The only exception was a free-look period available immediately after policy issuance. The argument at that time for PFRDA was that this rigid rule was required for “long-term old-age income security for subscribers”.

India-Brics trade booms to \$416 billion, but deficit keeps rising

NEW YORK.(Agency)
India’s trade with Brics countries gathered pace over the past five years, making the bloc a significant part of the country’s imports. However, this growing trade also reflects a bigger problem: India is relying more on imports from the bloc, pushing its trade deficit higher.
A report by Rubix Data Sciences said India’s bilateral trade with the other 10 Brics countries touched \$416 billion in CY2025, growing at nearly 10% every year between CY2021 and CY2025. But while trade has increased, India’s goods trade deficit with the bloc has nearly doubled in the same period, rising from \$117 billion to \$224 billion.
A big reason for this is the sharp jump in imports. India’s imports from Brics nations stood at \$320 billion in CY2025, growing at a 12% CAGR over five years. This also pushed Brics’ share in India’s total imports from 36% in CY2021 to 43% in CY2025.Within Brics, Russia became one of India’s fastest-growing import partners, with imports rising at a 61% CAGR, mainly because of crude oil purchases. The UAE and Brazil also remained major trade partners, each recording 12% CAGR growth. Exports, however, have not kept pace.
India’s exports to Brics countries reached \$96 billion in CY2025, growing at just 3% CAGR over the same period. Brics accounted for around 22% of India’s total exports. Among the bloc, exports to the UAE grew the fastest at 11%, followed by Russia at 8% and Egypt at 5%.This gap between imports and exports has widened India’s trade imbalance with several Brics members.

Govt levies windfall gains tax on petrol exports; slashes levy on diesel, jet fuel

The impact of the US-Iran war was finally felt on the retail prices of petrol and diesel when the oil marketing companies were allowed to raise prices of these two fuels by more than Rs 3 per litre. The latest measure is the imposition of the windfall tax.

New Delhi,.(Agency)
The government has imposed windfall gains tax of Rs 3 per litre on the export of petrol. On the other hand, it reduced the levy on diesel to Rs 16.5 per litre and jet fuel or ATF (aviation turbine fuel) to Rs 16 per litre. The new charges will be effective from Saturday, May 16. As the

nomenclature indicates, windfall tax is defined as a temporary tax levied by governments on industries which witness unexpected surges in profitability. These are typically caused by geopolitical crises and/or supply chain bottlenecks. The idea is to earn from the taxes of super-profits or windfall gains during times of higher global prices. This is a tool for governments to regulate the trade deficit. The decision was announced less than 24 hours after the decision to raise retail prices of petrol and diesel.
Special additional excise duty
The windfall tax has come as a Special Additional Excise Duty. It is adjusted every fortnight by the government based on fluctuations in international crude oil prices. The special additional excise duty on petrol at Rs 3 per litre comes for the first time since the hostilities began on February 28 in West Asia when US forces attacked Teheran. The objective of the windfall tax is to rein in exporters from taking undue advantage of the price

differences, as globally crude oil prices have surged from about \$70 a barrel to more than \$110 a barrel.



Export duty on diesel and jet fuel
The duty on export of diesel was Rs 23 per litre, which has now been reduced to Rs 16.5 per litre. The duty on export of jet fuel was Rs 33 per litre but has been reduced to Rs 16 per litre. As the war progressed and prices of crude oil jumped in the global markets, the Centre imposed an export duty on diesel at Rs 21.50 a litre, and on ATF at Rs 29.5 a litre on

March 26. When it was reviewed on April 11, the export duty on diesel was raised to Rs 55.5 per litre and that on jet fuel to Rs 42 per litre. The duties were slashed to Rs 23 per litre on diesel and Rs 33 per litre on jet fuel when the government reviewed the rates on April 30.
Retail prices raised, more can follow
The impact of the US-Iran war was finally felt on the retail prices of petrol and diesel when the oil marketing companies were allowed to raise prices of these two fuels by more than Rs 3 per litre. The price rise happened after a gap of four years. The latest measure in the petro-fuels domain is the imposition of the windfall tax. In April, the government cut excise duty on petrol and diesel by Rs 10 a litre to provide relief to the oil marketing companies which were getting sandwiched between galloping crude oil prices and an unaltered retail fuel price line.

Sensex, Nifty slide over 2% amid crude surge, geopolitical tensions

New Delhi.(Agency)
Domestic equity markets witnessed another week of sharp correction, with benchmark indices declining over 2 per cent each amid rising crude oil prices and ongoing geopolitical tensions in West Asia. Nifty declined by 2.2 per cent or 532 points during the week to close at 23,643.5 against the previous Friday’s closing, while Sensex dropped 2.7 per cent or over 2,000 points to end at 75,238.Meanwhile, broader markets remained under heavier pressure, with the mid-cap index falling over 2 per cent and the small-cap index losing nearly 4 per cent.Sectorally, realty stocks were worst performers, with BSE Realty plunging almost 8 per cent.Meanwhile, IT stocks also remained under pressure, with the BSE IT index falling 5.7 per cent, followed by auto, capital goods and consumer durable shares.In addition, banking and PSU stocks also witnessed selling pressure, with the BSE Bankex and BSE PSU indices declining 3 per cent each.However, few defensive sectors

outperformed, with BSE Metal gaining 1.5 per cent, while healthcare stocks rose 1.4 per cent.
Also Read: India-UAE Ink LPG, Strategic oil reserve deals amid US-Iran war fearsFrom the 30-scrip basket, Titan



Company was the top loser, falling 7.6 per cent, followed by Reliance Industries, Tech Mahindra and Mahindra & Mahindra.According to market experts, investor sentiment remained cautious amid the lack of meaningful de-escalation in West Asia tensions and their impact on crude oil

prices, inflation and the rupee. They said elevated crude prices, rising global bond yields and sustained strength in the US dollar continued to pressure emerging markets, leading to intermittent foreign fund outflows and currency weakness.Analysts further noted that higher wholesale inflation, fuel price pass-through and elevated bond yields have increased concerns over macroeconomic stability and future monetary policy actions.
In addition, global cues also remained negative as tensions in West Asia continued without any breakthrough.
Moreover, concerns over disruptions in the Strait of Hormuz kept Brent crude oil prices elevated in the USD 105-110 per barrel range.Despite the correction, domestic institutional investors continued to provide support to the market, aided by strong retail participation.Additionally, SIP inflows in April stood at Rs 31,115 crore, helping absorb sustained FII selling.

SEBI relaxes borrowing norms for InvITs above 49% leverage limit

New Delhi,.(Agency)
Securities and Exchange Board of India (SEBI) on Friday relaxed borrowing norms for Infrastructure Investment Trusts (InvITs) with leverage exceeding 49 per cent of asset value, a move aimed at expanding financing flexibility for infrastructure projects and improving funding access across the sector. In a circular, the market regulator said InvITs will now be allowed to raise fresh borrowings above the 49 per cent leverage threshold for capital expenditure intended to enhance asset performance or expand project capacity.The regulator has also permitted InvITs to use additional debt for major maintenance expenses related to road infrastructure projects.According to the circular, such expenses will include non-routine maintenance obligations mandated

under concession agreements.“Major maintenance expense shall mean expenditure incurred on maintenance of road project which is not routine maintenance and is in accordance with



the obligations and requirements specified in the concession agreement,” SEBI said. The relaxation is expected to particularly benefit road-focused InvITs that require significant funding for large-scale repairs and periodic maintenance

work.SEBI has also allowed refinancing of existing debt by InvITs, special purpose vehicles and holding companies under specified conditions.The market regulator clarified that refinancing would be restricted only to the principal amount of the original borrowing, while accumulated interest, penalties, fees or other charges cannot be refinanced.
“Only the principal portion of debt is refinanced, that is, any accumulated interest or any charges or fees by whatever name called shall not be refinanced,” the regulator said.The revised framework follows amendments introduced to Regulation 20(3)(b)(ii) of the SEBI InvIT Regulations on April 17, 2026, which broadened the permitted use of borrowings beyond the leverage ceiling.

PFRDA’s new NPS rules: Retirees can now withdraw up to 80% corpus after retirement

The Pension Fund Regulatory and Development Authority issued a circular on May 15, 2026, formally launching the Retirement Income Scheme alongside several new post-retirement drawdown mechanisms.

New Delhi.(Agency)
India’s pension regulator has overhauled the way National Pension System subscribers can access their retirement savings, introducing a set of new options designed to give retirees meaningful control over how and when they draw down their corpus.The Pension Fund Regulatory and Development Authority issued a circular on May 15, 2026, formally launching the Retirement Income Scheme alongside several new post-retirement drawdown mechanisms. The core objective is straightforward: move away from a one-

size-fits-all payout model and allow subscribers to structure withdrawals around their actual financial needs in retirement.The most significant structural shift involves the annuity requirement for private-sector and non-government subscribers. Previously, retirees were required to deploy 40 percent of their accumulated corpus into an annuity product that pays a fixed income for life, leaving 60 percent available for lump sum withdrawal. That ratio has now been inverted. Under the revised framework, the mandatory annuity floor drops to 20 percent, freeing up to 80 percent of the corpus for lump sum or phased withdrawal. The regulator has been explicit that the new drawdown options sit alongside the annuity requirement rather than replacing it — subscribers must still purchase an annuity with the minimum mandated portion.For subscribers whose total corpus does not exceed Rs 8 lakh, the annuity requirement is waived entirely,

allowing full withdrawal. Those with a corpus between Rs 8 lakh and Rs 12 lakh can withdraw up to Rs 6 lakh as a lump sum, with the remainder channelled into annuity or structured withdrawal products.



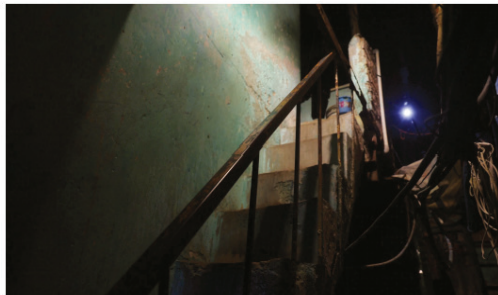
New Withdrawal Instruments
Two new withdrawal tools have been introduced to support phased drawdown. The Systematic Lump Sum Withdrawal allows retirees to pull money out in instalments over a defined period rather

impact on retail fuel prices within the country. The differential taxation strategy is expected to boost government revenue from petroleum exports without affecting price stability for Indian consumers.This marks the latest fortnightly revision in export duties, a mechanism introduced after levies were first imposed on March 27, 2026, amid global supply uncertainties stemming from West Asia tensions. The government has periodically calibrated these duties—previously reduced for diesel and ATF effective May 1, to balance domestic availability, discourage excessive exports when international prices are attractive, and prevent windfall gains for exporters at the expense of local supply.Experts note that the adjustment, particularly the introduction of a modest duty on petrol exports (which was previously nil), could moderately impact margins of export-oriented refiners such as Reliance Industries, while public sector oil marketing companies with a stronger domestic focus may see limited effects. The policy continues to prioritise fuel security for Indian consumers by making exports relatively less lucrative.
Officials have maintained that such flexible tools like SAED allow the Centre to respond swiftly to volatile global crude markets



Robert Vadra appeared before court after summons in the Enforcement Directorate case linked to alleged money laundering in the Shikohpur land deal in Haryana.

Yet, even after 25 years, India has not based major warships, fighter aircraft, submarines or long-range Anti-Submarine Warfare (ASW) aircraft on these islands. Common reasons include a lack of fuel storage facilities, docking and repair facilities for warships and submarines. It is a chicken and egg conundrum.



"Thought He Could Hide": Trump Says Top ISIS Leader Abu-Bilal Killed

US President Donald Trump said Friday that American and Nigerian forces had killed a senior Islamic State group leader. "Tonight, at my direction, brave American forces and the Armed Forces of Nigeria flawlessly executed a meticulously planned and very complex mission to eliminate the most active terrorist in the world from the battlefield," Trump said on Truth Social. "Abu-Bilal al-Minuki, second in command of ISIS globally, thought he could hide in Africa, but little did he know we had sources who kept us informed on what he was doing," he added. Al-Minuki had been placed under US sanctions in 2023 for ties to the Islamic State group. "He will no longer terrorize the people of Africa, or help plan operations to target Americans," Trump said. "With his removal, ISIS's global operation is greatly diminished."

Aerospace giant Boeing on Friday confirmed that China had committed to purchasing 200 aircraft, as previously announced by US President Donald Trump during his visit to Beijing. "We had a very successful trip to China and accomplished our major goal of reopening the China market to orders for Boeing aircraft," the company, whose CEO Kelly Ortberg was part of the US delegation to China, said in a statement. "This included an initial commitment for 200 aircraft and we expect further commitments will follow after this initial tranche," Boeing said, thanking the Trump administration "for making this milestone happen." "We now look forward to continually addressing China's aircraft demand," it said. China's last order from Boeing dates back to 2017, when Trump went to Beijing at the start of his first White House term. At that time, it ordered 300 single-aisle and wide-body planes -- a mega-deal valued at \$37 billion.

On Thursday, Trump had referred to the new Boeing commitment, telling Fox News host Sean Hannity in an interview: "I think it was a commitment."

"That's a lot of jobs," the president added.

Speaking to reporters aboard Air Force One as he flew home from China, Trump said the deal included "a promise of 750 planes, which will be by far the largest order ever, if they do a good job with the 200." US media have reported for several months that Beijing was poised to make a major order from Boeing that would include 500 single-aisle 737 MAXs and about 100 larger 787 Dreamliners and 777s.

The latest online drama involving Lil Tjay and Kai Cenat has once again blurred the line between entertainment and personal privacy. What began as subtle tension between two internet personalities quickly exploded after Lil Tjay briefly posted screenshots of private messages connected to Cenat's former girlfriend, Gigi Alayah. Although the posts disappeared within hours, the internet had already captured everything. Screenshots spread rapidly across X and Instagram, sparking fierce arguments among fans over whether the rapper crossed a line or simply added another chapter to an already public feud.

Lil Tjay sparks backlash after sharing Kai Cenat-related messages

The controversy began after Lil Tjay uploaded screenshots of direct messages allegedly involving Gigi Alayah. Some of the conversations reportedly dated back several years, while one message from May 12 read, “Don't just open my shit crazy.”

The deleted uploads instantly triggered heavy criticism online. Many fans accused the rapper of unnecessarily dragging private conversations into public view, especially since Kai Cenat had recently stepped away from livestreaming following news of his breakup. Social media reactions became sharply divided. Some users called the move immature and attention-seeking, while others defended Lil Tjay's right to share interactions tied to ongoing public tension. The situation intensified because the rapper and Cenat have exchanged indirect shots before. Even though neither side publicly escalated the issue immediately afterward, online communities quickly turned the incident into another major celebrity internet debate. At the same time, observers pointed out that Lil Tjay has remained surrounded by controversy throughout recent months. Alongside releasing new music and making talk-show appearances, the rapper has also been linked to public disputes involving other artists, including Real Boston Richey. Kai Cenat remains silent as Lil Tjay controversy fuels speculation. While Lil Tjay briefly controlled the online conversation, Kai Cenat chose not to respond publicly.

Israel and Lebanon agreed to extend a ceasefire and hold expanded talks on a political settlement, the United States announced Friday, even as Israel carried out new strikes that it insists are not subject to the truce. Israel has been pounding Lebanon and invaded its south in response to fire from Hezbollah, the Iranian-backed Shia movement that is not part of the ceasefire diplomacy. Envoys from Israel and Lebanon's government, which has struggled to restrain Hezbollah, met for two days in Washington and said they would extend the ceasefire that was set to expire Sunday. The cessation of hostilities "will be extended by 45 days to enable further progress," State Department spokesman Tommy Pigott said.

He said that the State Department would hold negotiations aimed at reaching a permanent political agreement on June 2 and 3 and that the Pentagon would bring together delegations from the countries' militaries on May 29. Lebanon's delegation said in a

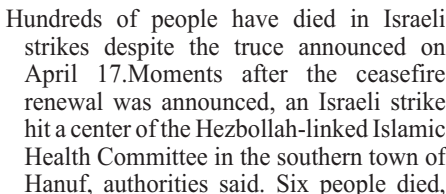
statement that the ceasefire extension and opening of military talks would offer "critical breathing room for our citizens" with a goal of "lasting stability." In an implicit rebuke to Hezbollah, Lebanese Prime Minister Nawaf Salam told an NGO dinner in Beirut that his country has had "enough of these reckless adventures serving foreign projects or interests."

The latest brought "a war we did not choose but was forced upon us, which led to Israel occupying 68 towns and villages," he said.

The United States steadfastly backs Israel, with which it launched attacks on Iran on February 28, but has also gently voiced unease about Israeli troops' encroachments into southern Lebanon. Israel's ambassador to Washington, Yechiel Leiter, who led his country's delegation, said after the talks that the priority was ensuring Israel's security. "There will be ups and downs, but the potential for success is great," Leiter wrote on X.Iran's clerical state, Hezbollah's

patron, has demanded a lasting ceasefire in Lebanon before any peace agreement with US President Donald Trump, who has been frustrated by Tehran's refusal to an accord on his terms.

Truce met with violence



including three paramedics, according to the Lebanese health ministry. Israel also carried out strikes in the southern city of Tyre after issuing evacuation orders, and Hezbollah said it targeted Israeli barracks in the northern city of Kiryat Shmona with drones. Lebanon's health ministry said strikes in the Tyre district also wounded at least 37 people, including six hospital personnel, nine women and four children.

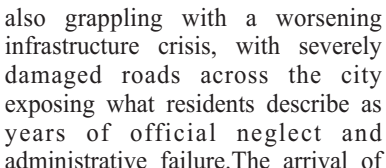
Hafez Ramadan, a resident near the building targeted by the airstrike, said it had housed people who had fled their towns due to the war and was adjacent to a hotel where more displaced were staying. "There are only women, children and the elderly here," he said. "Because of this strike, people have been displaced again." The Israeli military said another of its soldiers was killed in southern Lebanon, bringing the number of Israeli soldiers killed in clashes with Hezbollah since early March to 19. A civilian contractor was also killed.

Four people were killed and one was injured in two separate bridge collapse incidents in Pakistan's Sindh province on Friday, according to ARY News.

In one of the incidents, a section of the under-construction Ghotki-Kandhkot Bridge collapsed after a heavy portion of the structure gave way and fell, ARY News reported, citing local sources. The incident triggered concern among residents, who questioned the quality of construction material used in the project and raised allegations of possible corruption.

Meanwhile, in another incident, four labourers were killed while one was left injured in Sindh's Karampur when a section of the dilapidated old bridge over Naseer canal collapsed, as per ARY News. As per locals, the construction work on the new bridge was underway when the old bridge collapsed and delay in rescue operations was also reported after emergency teams failed to reach the incident spot for several hours after

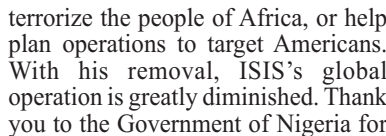
the incident. The rescue teams confirmed recovery of four bodies from rubble of the bridge; meanwhile, the other labourer was admitted to the hospital for treatment. Apart from the bridge collapse incident, Karachi is



US President Donald Trump announced on Friday (local time) that American forces, along with the Nigerian armed forces, had eliminated Abu-Bilal al-Minuki, the second-in-command of ISIS globally, in Nigeria. In his Truth Social post, Trump wrote, "Tonight, at my direction, brave American forces and the Armed Forces of Nigeria flawlessly executed a meticulously planned and very complex mission to eliminate the most active terrorist in the world from the battlefield. Abu-Bilal al-Minuki, second in command of ISIS globally, thought he could hide in Africa, but little did he know we had sources who kept us informed on what he was doing." Trump welcomed the killing of Al-Minuki, stating that he

would “no longer terrorize the people of Africa, or help plan operations to target Americans.”

Trump further added, "He will no longer



your partnership on this operation. GOD BLESS AMERICA!" Who was ISIS No 2 Abu-Bilal al-Minuki?

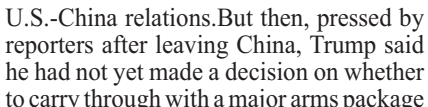
Abu-Balal al-Minuki was an alleged senior ISIS operative who reportedly served as the terror group's global second-in-command. He was also said to be known by the name Abu Bakr ibn Muhammad ibn Ali al-Mainuki. According to a report by the Counter Extremism Project, Al-Mainuki primarily operated in Africa's Sahel region, which stretches across 12 countries. The Sahel is a semi-arid transitional belt extending nearly 5,900 kilometres from the Atlantic Ocean to the Red Sea, separating the Sahara Desert in the north from the Sudanian savannas in the south.

For three days in China, President Donald Trump was unusually quiet, not speaking to reporters much and even mostly staying off social media. Then he got on his plane home and unloaded. Trump's trip was unexpectedly dominated by discussions about Taiwan and the notion that Washington and Beijing could adopt a new framework for managing their complicated relationship. Chinese President Xi Jinping kicked off the whirlwind visit with a warning: If Washington mishandles its relations with the self-governing island of Taiwan, the U.S. and China could end up clashing or even in open conflict.

Trump did not respond publicly, refraining from mentioning Taiwan while in Beijing. But he suggested aboard Air Force One on his way home that Xi's staunch opposition might make him rethink a planned U.S. arms sale to Taipei. Among the other topics of discussion were trade and the U.S. and Israel's war in Iran, which had been expected to take up most of the attention.

Trump spent the trip overtly flattering China's leader, despite Xi not reciprocating. And the president did not push back publicly on China's characterization that he and Xi had agreed to a "constructive" new vision for dealing with their relationship issues. Trump held his tongue on Taiwan — until he was headed home. Before the trip, Trump demonstrated greater ambivalence toward Taiwan in his second term, raising questions about whether he might be open to dialing back support for the island democracy that Beijing views as its breakaway province. Secretary of State Marco Rubio insisted there was no change in the U.S. approach to Taiwan. But there was always a risk that Trump — not known for diplomatic nuance — might make an off-the-cuff

remark that could have mammoth ramifications for Taiwan. In the end, Trump said nothing publicly about Taiwan, even as his Chinese counterpart suggested the island was the most important aspect of



sale he previously approved for Taiwan after hearing Xi's objections.

Trump's Republican administration in December authorized an \$11 billion weapons package for Taipei, but it has yet to move forward. Lawmakers also approved a \$14 billion arms sale to Taiwan in January, but the sale cannot advance until Trump formally sends it to Congress.

"President Xi and I talked a lot about Taiwan," Trump told reporters on the presidential plane. He said China's leader "does not want to see a fight for independence because that would be a very strong confrontation."

"I heard him out," Trump said. But "I didn't make a comment." Trump appeared to struggle to recall the name of Taiwanese President Lai Ching-nan, "The last thing we need right now is a war that's 9,500 miles away."

NEWS BOX

Brand Beckham soars: David Beckham becomes UK's first billionaire sportsman

New Delhi. (Agency)

David Beckham, the boy from Leytonstone who once conquered world football with a swing of his right boot, has achieved what no British athlete before him ever could: the ten-figure club. According to the latest iteration of the Sunday Times Rich List, David and Victoria Beckham have officially crossed the threshold into billionaire status, with their collective net worth skyrocketing to a staggering £1.185 billion. The valuation marks a seismic leap from their estimated £500 million fortune last year, making Beckham the UK's first-ever billionaire sportsman. While the "Brand Beckham" machine has been a lucrative global enterprise for three decades, this recent financial surge is rooted firmly in a masterstroke of American sporting real estate and a slice of Argentinian magic.

THE MESSI FACTOR

The crown jewel of Beckham's empire is Inter Miami CF. When Beckham signed for the LA Galaxy in 2007, his contract included a revolutionary clause allowing him to buy an MLS expansion franchise for just \$25 million. Today, that franchise is valued well north of £1 billion. The catalyst for that exponential valuation jump was the historic signing of Lionel Messi, which sent global merchandise sales, ticket prices, and Apple TV broadcast subscriptions into orbit. Combined with massive real estate developments surrounding the club's upcoming Miami Freedom Park stadium, Beckham's gamble on American soccer has paid off in historic fashion. Yet, it is not a solo victory. The milestone represents a twin-engine financial triumph for Britain's ultimate power couple. Victoria Beckham's luxury fashion and beauty house, which faced well-documented financial headwinds for years, has engineered a dramatic U-turn. The label recently reported revenues breaching the £100 million mark, pivoting into serious profitability and silencing high-fashion skeptics. are as diversified as they are deep.



They funded their own dreams. Now Netherlands women are ready to play a World Cup

✦ The Netherlands are all set to make their Women's T20 World Cup debut next month in England and Wales. In an exclusive conversation with IndiaToday.in, Dutch skipper Babette de Leede reflected on the team's remarkable journey, from once struggling for recognition and resources to now stepping onto cricket's biggest stage.

New Delhi. (Agency)

2014 remains one of the most unforgettable years in Dutch cricket history. Under Peter Borren, the Netherlands men's team scripted a miracle at the T20 World Cup, storming into the Super 10 after chasing 190 against Ireland in just 13.5 overs in Sylhet. More than a decade later, Stephan Myburgh's breathtaking 23-ball 63 still lives vividly in memory, not just as one of their best, but as one of the most astonishing run-chases the tournament has ever witnessed. In that very

World Cup, the Dutch pulled off another remarkable victory, bowling England out for just 88 runs in a stunning display. But while the men were making headlines and inspiring a generation, in the same year, the Dutch women's team was simply trying to survive. They did not even have T20I status then and, instead of earning from the game, many players often dipped into their own pockets just to continue playing the sport they love. There was no full-time head coach either, a painful reminder of how little support surrounded women's cricket in the country at the time. It was amid that uncertainty that a 15-year-old Babette de Leede made her debut for the Netherlands in 2014, carrying little more than hope and a dream. 12 years later, that young girl now stands at the heart of a historic moment, preparing to lead the Netherlands into their maiden Women's T20 World Cup under full-time coach Neil McRae. What once felt distant and fragile has finally turned into something beautifully real for Dutch women's cricket. I made my debut earlier in

2014, but we didn't have T20I status back then. We've come a long, long way since. Back then, we had to pay for our own tours and trips, and our coach wasn't full-time. Gradually, things improved. Around 2019 or 2020, we got our first full-time head coach,

some of the girls are on part-time contracts as well," Babette said.

THE HAPPY MOMENT OF SHIVERS

Crickets has always flowed through the veins of the De Leede family. Babette's uncle, Tim de Leede, etched his name into Dutch cricket folklore during the World Cup 2003 when he produced a Player of the Match performance against India and even dismissed the great Sachin Tendulkar as his very first international wicket. Her cousin, Bas de Leede, has already carried the family legacy onto the ODI and T20 World Cup stages. Now, another chapter is ready to be written. Babette is preparing to represent the Netherlands at one of cricket's grandest events in England and Wales, adding her own story to a family that has long served Dutch cricket with pride. Earlier this year in Nepal, the Netherlands women scripted a remarkable run at the Qualifiers, winning five consecutive matches to book their place at the global event alongside Bangladesh.

who worked a lot with us and helped us get better," Babette told IndiaToday in an exclusive interview.

"We also started receiving match fees or at least petrol money, so it didn't cost us to play cricket or attend training. Now we're at a stage where we earn match fees on tour, and

opposite end, Saira Jabeen also played a fluent hand. Sana brought up the record-breaking milestone with a couple off the bowling of Zimunu in the final over before finishing unbeaten on a stunning 62 from only 19 deliveries, an innings decorated with 10 fours and two sixes. Jabeen remained not out on 50 from 32 balls as Pakistan piled up 223/4, their second-highest total in Women's T20Is. Zimbabwe never threatened in reply and were dismissed for 90. Pakistan's bowling unit dominated, with Sadia Iqbal and Nushra Sandhu sharing five wickets, while Sana also chipped in with 1/28.

Sana has enjoyed a sensational run in T20Is this year. She is currently Pakistan's leading run-scorer in the format in 2026, amassing 229 runs in five innings at a strike rate above 206. Earlier this year, she also produced her career-best T20I score — a blistering 90 off 41 balls against South Africa.

Pakistan's Fatima Sana scores fastest Women's T20I fifty, smashes Richa Ghosh's record

New Delhi. (Agency)

Fatima Sana etched her name into the record books after smashing the fastest half-century in Women's T20I history during Pakistan's third T20I against Zimbabwe in Karachi. The Pakistan skipper raced to fifty in only 15 deliveries, surpassing the previous benchmark of 18 balls jointly held by Sophie Devine, Phoebe Litchfield and Richa Ghosh. The Indian wicketkeeper scored her fifty off 18 balls during the clash against the West Indies on December 2024. Her breathtaking knock also equalled the fastest fifty recorded in all women's T20 cricket, matching feats achieved by Marie Kelly for Warwickshire in 2022 and Laura Harris for Otago in the 2025 Super Smash. Before Sana's blitz, Pakistan's quickest T20I fifty belonged to Nida Dar, who had reached the landmark in 20 balls against South Africa in 2019.



one over. The real carnage arrived in the 19th over against Nomvelo Sibanda. Sana unleashed a sequence of 4, 4, 6, 6 and 4, plundering 24 runs from the over and moving to 48 from just 14 balls. At the

quality pace hitter, I think it's him," Ashwin said, underscoring Dhoni's enduring value to a middle order that has occasionally lacked late-innings impetus.



"Let's see. I have a feeling that against SunRisers Hyderabad, there is a good chance of him playing. Let's wait and see how it goes." Whether the former captain can provide the fairytale finish to an

otherwise frustrating season remains to be seen, but according to Ashwin, the medical green light is imminent. "As far as I have heard, he has been ready to take the field for the last two-three games," Ashwin said.

ASHWIN DEFENDS CHENNAI AMID INJURY WOES

Addressing the inevitable scrutiny that accompanies the prolonged rehabilitation of a high-profile athlete, Ashwin came to the defence of the Chennai team management. He dismissed the notion that skipper Ruturaj Gaikwad or head coach Stephen Fleming could have managed the situation differently, pointing instead to the complex realities of modern sports science.

"I think the more you cut down on training, the chances of getting injured increases. Some, in a bid to avoid injuries, they look at hopping from match to match—that's wrong. But this is another department; it's physiotherapy and sports science. I don't think the coach and the captain can be blamed. They can't do anything," Ashwin explained.

South African legend, in a tweet, said that the note celebration isn't trending anymore and it never was in fashion.

"Time to put the papers away. It ain't trending no more. Actually, to be honest, never really was," said Steyn on X.

WHY DID AKASH PULL OFF NOTE CELEBRATION?

During the match, Justin Langer was quizzed about the celebration from Akash by the commentators and he said that he wasn't aware of it and it was something they will need to look into.

But, Akash then revealed it after the end of the first innings, saying that there was no reason behind and the chit was there to act as motivation for him. "It just gives me motivation. There is no reason behind it. Whatever motivates me during the game, I'll keep backing it," said Akash. It will be interesting to see if the players will now heed to Steyn's advice and look for a new celebration during matches.

MS Dhoni set for CSK return vs SunRisers in Chennai? Ex-teammate drops big hint

LOS ANGELES. (Agency)

The lingering mystery surrounding MS Dhoni's complete absence from the ongoing Indian Premier League season has taken a compelling turn, with veteran Indian spinner Ravichandran Ashwin hinting that the legendary wicketkeeper-batter could finally make his heavily anticipated return in Chennai Super Kings' must-win encounter against SunRisers Hyderabad on Monday. Dhoni, who has not played a single match in Chennai's 12 fixtures so far this season due to a calf injury sustained during pre-season training, left fans crestfallen yet again on Friday night. Despite travel arrangements being made for him to join the squad in Lucknow, the 44-year-old ultimately stayed back in Chennai as CSK fell to a damaging seven-wicket defeat against Lucknow Super Giants. However, speaking on his YouTube channel, Ashwin offered a reassuring assessment of Dhoni's physical state, suggesting that a return to the playing XI at Chepauk on Monday is firmly on the horizon. "Even now, if we talk about a

✦ Akash Singh flashed a handwritten note after striking against CSK in Lucknow. But Dale Steyn wasn't too pleased with the celebration, claiming that flashing the note was never a trend in the first place.

Dharamsala. (Agency)

Is the note celebration in IPL becoming outdated? Dale Steyn certainly thinks so, and he made his feelings felt right after Akash Singh pulled out a piece of paper with a message during the LSG vs CSK game at the Ekana Stadium on May 15. LSG vs CSK, IPL 2026: Highlights | Scorecard

Akash played his first match of the season and rocked the CSK top order by picking the

wickets of Ruturaj Gaikwad, Sanju Samson and Urvil Patel. Right after the wicket of Ruturaj, he pulled off the note that read, 'This trend started last year when Abhishek Sharma delivered a message for the SRH

fans and it has continued this season with Raghu Sharma first doing it and then Urvil Patel showing a message dedicated to his dad. But by the time Akash pulled it off, Steyn said it was time to put the papers away. The

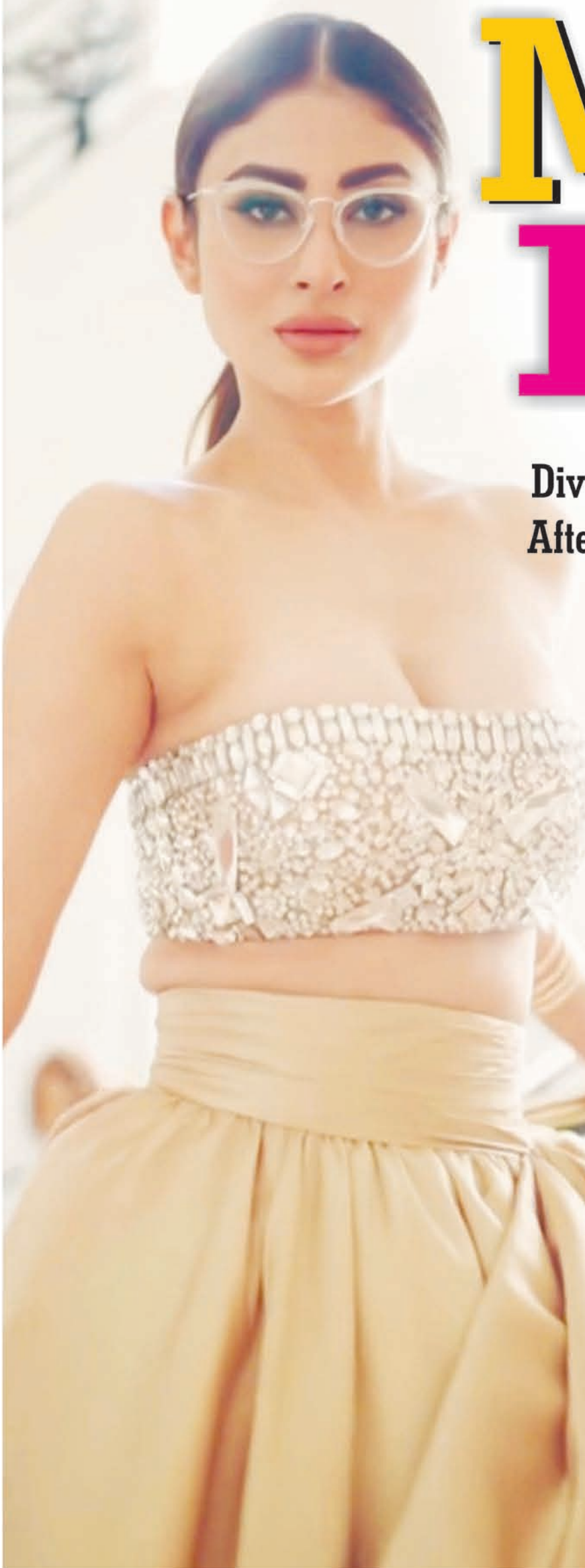
8 sixes in 16 balls: Lack of clarity gets the better of CSK against Lucknow



NEW DELHI. (Agency)

In two separate instances during the match against Lucknow Super Giants, Chennai Super Kings conceded four sixes in four balls. In a defence of 187 runs at the Ekana Stadium in Lucknow, that proved fatal for the Ruturaj Gaikwad-led side, who were chasing a top-four spot in the Indian Premier League's 2026 season. After a slow start to the season, Chennai had finally begun to put together some consistent results. Four wins from their last five games meant that CSK still had an outside chance of qualifying for the playoffs. However, it all came crashing down on Friday when Chennai were blown away by a magnificent 90-run innings from Mitchell Marsh, who looked in imperious touch on May 15. Playing on a deck that had good bounce and carry for the seamers, Marsh slammed seven sixes and nine boundaries before getting run out in the 12th over of the game. But by the time Marsh departed, the damage had already been done. In today's IPL Play of the Day, we look at how a stretch of 16 balls ruined CSK's night at the Ekana Stadium on May 15.

On Friday, Chennai Super Kings' fast bowlers had one clear task: find the length that helped LSG pacers make life miserable for Chennai's top order in the first innings. It seemed to be the hard-length area where Lucknow's pacers operated, extracting enough skid and bounce to hurry multiple batters into mistakes. Young Kartik Sharma and Shivam Dube had played valuable knocks to get CSK to a fighting total of 187. The bowlers simply needed to target the same areas and test the LSG batters early in the innings. But that plan quickly fell apart as Mitchell Marsh took a liking to the CSK pacers and dismantled them on Friday. Marsh's incredible assault began in the fifth over of the match when he took Anshul Kamboj apart with four consecutive sixes.



Mouni Roy

Divorce: Actor Turns Off Comments Section After Fans Troll Disha Patani On Instagram

Actress Mouni Roy has turned off her comments section after announcing her divorce from Suraj Nambiar. On Thursday, the couple confirmed their divorce in a joint post in which they confirmed they are parting ways and requested privacy. The actress soon turned off her comments section and hid the existing comments. Currently, no comments are visible on the joint post. While social media users, who couldn't comment on the recent post, swarmed to Mouni Roy's older posts. They dragged Disha into the marriage controversy surrounding Mouni and Suraj, and accused her of being the home-wrecker.

One user wrote, "Karwa Di mouny our suraj ke bich ladai (You instigated the fight between Mouni and Suraj)". Another user wrote, "Divorce ke baad new husband Disha (After divorce, the new husband will be Disha)".

The couple wrote in their post, "We note with dismay the unnecessary and intrusive attention into our personal lives by certain quarters of the media. We would like to state that we have decided to part ways and are taking the necessary time to address matters privately and amicably. Attempts have been made to sensationalise our private lives by the circulation of fictitious narratives and blatant falsehoods, which do not reflect the reality of our relationship". They further mentioned, "After thoughtful reflection on evolving personal priorities, we have mutually chosen to move forward on separate paths with respect and understanding. At this point, we are focused on navigating this phase thoughtfully and privately. We will endeavour to cherish our friendship in times to come. We sincerely appreciate your understanding, respect for our privacy, and the continued support extended to us during this time".

For the uninitiated, Mouni Roy's personal life has been under the scanner for the past few days. The speculation began after many noticed that Mouni and her husband, Suraj Nambiar, appeared to have unfollowed each other on Instagram, sparking concerns about a possible separation.

Mouni and Suraj first crossed paths at a New Year's celebration in Dubai in 2018. Introduced through mutual friends, the two quickly formed a close connection. In the early stages of their relationship, distance proved to be a challenge, with Suraj living in Dubai and Mouni based in Mumbai. Despite being in a long-distance relationship, they made constant efforts to spend time together, frequently travelling to meet one another. The couple tied the knot in 2022 in a Malayali wedding ceremony followed by a Bengali one in Goa.



Abhishek Bachchan's Villain Avatar From Shah Rukh Khan's King LEAKED



Shah Rukh Khan and Deepika Padukone's actioner King is among the most-awaited films of 2026. Helmed by Siddharth Anand, the film also stars Abhishek Bachchan, Suhana Khan, Raghav Juyal, Saurabh Shukla and Rani Mukerji in pivotal roles. The film recently grabbed attention after videos of SRK and Deepika from the sets of King were leaked online. Now, amid the growing curiosity surrounding the project, fresh glimpses from the shoot have surfaced, this time featuring Abhishek Bachchan, who is reportedly set to play the antagonist.

The team was busy shooting for the next schedule in South Africa recently. However, it is not confirmed if the visuals of Abhishek Bachchan are from Cape Town or somewhere else. In the leaked pictures, he is seen standing atop a vehicle while holding a shotgun. Set against a rugged mountainous backdrop, the actor sports a dark outfit layered with a long grey overcoat, adding to the intense and gritty vibe of the scene.

Reportedly, King Khan, along with the team, had recently flown to South Africa to film a song sequence along with crucial climax portions of the movie. Following an extensive two-week schedule overseas, the team returned to Mumbai to continue shooting the next phase of the big-budget action entertainer.

Meanwhile, SRK and Deepika's leaked visuals from the sets earlier left their fans in awe. The moment was made extra special as Ranveer Singh and baby Dua were also seen watching them shoot the romantic song.

However, director Siddharth Anand urged everyone not to leak assets online. A statement read, "Request to all the fans. Please do not post or circulate any leaked multimedia from the sets of King. The team is working round the clock to ensure the best cinematic experience for everyone. Let us wait for the surprise on the big screen and for the assets to be revealed as the team of King originally intends to. Thank you for your love, support and cooperation."

Saif Ali Khan On Taking 'Blessings' From His Kartavya Poster: 'All The Best To The Movie'



There is a certain breezy self-awareness to Saif Ali Khan that the internet has quietly adored for years. Among younger fans, the actor has earned a reputation for being effortlessly Gen Z coded, someone who appears unbothered, witty, slightly chaotic in the best way, and refreshingly unserious about the heavy machinery of stardom.

Last week, Saif gave the internet yet another moment to obsess over. At the trailer launch of Kartavya on May 7, the actor unintentionally became part of one of the week's most shared viral clips. As he entered the venue, Saif was seen breaking into a small dance before seemingly "taking blessings" from his own poster. The clip immediately reminded fans of Kareena Kapoor Khan's iconic "Main Apni Favourite Hoon" energy, sparking memes and amused reactions across social media.

Saif Ali Khan Explains Viral 'Blessing' Moment
Saif has now reacted to the viral moment in a Netflix video and explained what was actually going on. According to him, the gesture was not as dramatic as the internet made it look, but came from a place of wishing the film and his character well.

He said, "See, the thing is, you walk on, there's this huge poster of Kartavya and this cop, who, you can see that I'm saying all the best to the movie, all the best to me playing that. The film, in many ways, what he's fighting for is his home and his family. When I read the script, I mean, he's got many amazing qualities and he's probably far more amazing than I am." The explanation only added to the charm of the moment, with fans once again pointing out how casually funny Saif can be without seeming to try.

Saif Ali Khan Explains Viral 'Blessing' Moment
Saif has now reacted to the viral moment in a Netflix video and explained what was actually going on. According to him, the gesture was not as dramatic as the internet made it look, but came from a place of wishing the film and his character well. He said, "See, the thing is, you walk on, there's this huge poster of Kartavya and this cop, who, you can see that I'm saying all the best to the movie, all the best to me playing that. The film, in many ways, what he's fighting for is his home and his family. When I read the script, I mean, he's got many amazing qualities and he's probably far more amazing than I am."



Sara Ali Khan

Reveals If Social Media Trolls Affect Her Mental Health Amid Ongoing Feud With Orry

Actress Sara Ali Khan opened up about dealing with trolls, online criticism, and the love she receives from the netizens on social media. Talking exclusively to IANS, Sara was asked if these social media comments end up having an impact on her mental health.

The 'Atrangi Re' actress admitted that she does get affected, as at the end of the day, as an actor, the primary focus is the audience. However, she pointed out that as time passes, one also learns to work for themselves. She told IANS, "I'll be lying if I say I don't get affected. I do get affected because ultimately, I, you know, do what I do for my audiences, and if I disappoint them, I don't feel good. But I think somewhere in this journey of having been here now for a while, you actually start also working for yourself. And I think I learned that late in my career." Sara further explained, "I think for very long the initial focus was, and it'll always be, I said 'Janata Janata' and I meant that. The focus will always be the audience. But if

you truly start enjoying your work, you enjoy the process, and you tell yourself, not in a lie but in a genuine way, that I have done my best. That absolves you of any sort of mental guilt and self-flagellation for no reason. Then you feel like, I did my best, I did as much as I could, and now it's up to God. That gets easier if you put in your



best, and then that's it."

Work-wise, Sara will be seen playing a crucial role in the upcoming romantic comedy "Pati Patni Aur Woh Do", with Ayushmann Khurrana, Rakul Preet Singh, and Wamiqa Gabbi in crucial roles, along with others. Directed by Mudassar Aziz, "Pati Patni Aur Woh Do" will be reaching the cinema halls on May 15.